हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जनवरी, 1974

(द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

बुधवार, 16 जनवरी, 1974

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 1
बहीर्गमन	(11) 20
अनुदानो के लिए सरकारी मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(11) 20

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 जनवरी, 1974 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1 चण्डीगढ में 14.00 वजे हुई । अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

वर्ष 1974– 75 का बजट–

अनुदानों के लिए सरकारी मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : All the demands are deemed to have been read and moved. Members raising discussion should indicate the number of the demands.

That a sum not exceeding Rs. 19,67,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 3,74,19.570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 8,37,92,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the

charges under Demand No. 3—Home Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,75,37,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No.4—Revenue Department.

That a sum not exceeding Rs. 94,69,070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 5—Excise and Taxation Department

That a sum not exceeding Rs. 2,70,60,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 6—Finance Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,64,12,306 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 19,52,26,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 8—Building and Roads Department.

That a sum not exceeding Rs. 27,84,80,170 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No.9—. Education Department.

That a sum not exceeding Rs. 13,97,27.370 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 10 Medical and Public Health Departments.

That a sum not exceeding Rs. 14,19,09,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 11—Urban. Development Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,62,27,090 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 12—Labour and Employment Departments.

That a sum not exceeding Rs. 2,60,20 770 he granted to the Governor to, defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 13—Social Welfare and Rehablitation Departments.

That a sum not exceeding Rs. 95,77,75.200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 14—Food and Supplies Department.

That a sum not exceeding Rs. 45,64,19,400 be granted to the Governor to to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the

charges under Demand No. 15—Irrigation Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,76,38 010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 16—Industries Department.

That a sum not exceeding Rs. 11,00,95,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 17—Agriculture Department.

That a sum not exceeding Rs. 3,30,92,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 18— Animal Husbandry Department.

That a sum not exceeding Rs. 24,72,980 he granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year; 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 19—Fisheries Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,38,01,970 be granted to the Governor to. defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 20—Forest Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,34,22,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 21—Community Development Department.

That a sum not exceeding Rs. 3,58,93,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year1974-75 in respect of the charges under Demaned No 22— Co-operation Department.

That a sum not exceeding Rs. 21,60,06,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demaned No 23—Transport Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,82,68,800 be granted to the Governor to defray the charges. that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 24—Tourism Department,

That a sum not exceeding Rs. 28,54,26,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 25—Loans and Advances.

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा– अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, तीन दिन बजट पर डिसकशन होने के बाद आज ये डिमांड्ज, 25 डिमांड्ज अन्डर डिस्कशन है । हाउस में गवर्नर एड्रेस पर और बजट पर छः दिन बहस हुई, और रोज एक नया ही एजेंडा डिसकस होता रहा

Mr. Speaker : Order please. Plea se indicate the number of the demand that you want to discuss.

श्री अमर सिह : मैं डिमांड्ज पर ही आ रहा हूं । मैं देख रहा हूं कि इन 25 डिमा– ड्ज में, चांद राम डिमांड, जिस पर डिस्कशन होता रहा, वह नही आई । स्पीकर साहब, मैं फूड एंड सप्लाई की डिमांड न. 14, इरीगेशन की डिमांड न. 15 इंडस्ट्री की डिमांड न. 16, ऐग्रीकल्चर की डिमांड न. 17, एजुकेशन की डिमांड नं. 9 और बिल्डिंग ऐंड रोडज डिमांड नं 8 के बारे में कहना चाहुंगा स्पीकर साहब, मैंने ये डिमांड्ज इसलिए बोली है कयोकि मैं इन सब को इकट्ठा लेकर अपने विचार रखना चाहता हूं स्पीकर साहब, जहां तक सूबे के विकास का इन डिमांड्ज के साथ ताल्लुक है, इसमें दो राय नहीं है कि स्टेट का विकास हुआ है विकास होना भी लाजमी था, क्योकि बहुत पहले जब सर छोटू राम जी, ज्वांयट पंजाब में रैवेन्यू मिनिस्टर होते थे, जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ये चारों इकट्ठे होते थे, तो कुल 9 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट होता था हरियाणा अलग बनने से पहले मार्च, 1966 में 3 अरब, 86 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ था लास्ट ईयर जब हमने इस सदन में बैठकर बजट पास किया तो यह राशि 4 अरब, 12 करोड़ रुपए की थी और इस साल 4 अरब 49 करोड़ का बजट पास किया है जब इतना रुपया खर्च हो तो लाजमी है कि हमारा विकास हुआ है । इतनी ज्यादा राशि जो खर्च मे आई है, रुससे विकास होना लाजमी था और विकास हुआ है। लेकिन, स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर और इरीगेशन डिपार्टमैंट के बारे में रीजनल– इम्बैलेंसिज को दूर करने की बात हाउस में कही गई है यह इम्बैलैन्स खत्म करना बहुत जरुरी है

क्योंकि अगर प्रांत का एक पार्ट प्रोडक्टिव न हो तो हमारे लिए शोभा नही देता । जिस प्रकार समाज में अगर एक आदमी का कोई अंग गड़बड़ वाला हो यास उसमे पीड़ा हो तो सारा शरीर काम नहीं करता, उसी तरह से समाज में अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ हो या वह किसी दूसरे पर डिपैन्ड करता हो तो समाज में उसका आदर होता । पिछड़ा हुआ वर्ग हमेशा पीछे रह जाता है क्योंकि उस पिछड़ेपन को समाज पुरा नहीं कर सकता । इसी प्रकार किसी प्रान्त का, किसी प्रदेश का, जो इलाका पिछडा हुआ रह जाता है उसमें हीन–भावना आ जाती है । वह प्रोडक्टिव एरिये से अलग रह जाता है उसमें तरक्की और उत्थान की कोई बात नहीं होती । इसलिए रीजनल इम्बैलंसिड खत्म करने के लिए इरीगेशन डिपार्टमैंट की तरफ से लोगों को जो इरीगेशन की फैसिलिटीज, जिन एरियाज को दी गई है, उस में मेरी कांस्टीच्यूऐसी भी शामिल है–बेशक उसमे भगाना माइनर शामिल न हो । रीजनल इम्बैलैसिज को खत्म करने के लिए इरीगेशन डिपार्टमैंट ने 45,64,19, 400 रुपए की राशि ली है । ऐग्रीकल्चर केलिए 11,00,95,600 रुपए मांगे है । स्पीकर साहब, सरकार रीजनल इम्बैलैसिज दूर करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए सरकार हाउस से पैसे पास करवा न्ही है । पानी के मामले में रीजनल इम्बैलैसिज तब दूर होगा जब रावी–व्यास का पानी आ जाएगा लेकिन इस वक्त रुरल और अर्बन इम्बैलैंसिज वाकी हैं । रूरल एरिया के अन्दर हम ऐग्रीकल्चर का नाम लेते है जव तक ऐग्रीकल्चर को पूरी सुविधाएं नही मिलेगी, ऐग्रीकल्चर पर डिपैड

करने वाले लोगों को पूरी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी तव तक तरक्की नहीं हो सकती और जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी तब तक सारे प्रदेश को तरक्की नहीं हो सकती ऐग्रीकल्चर के लिए 11,00,95,600 रुपए की राशि रखी है । जमींदारों को क्राप लोन मिलता है। डेरी डिवैल्पमैंट के लिए लोन मिलता है, सिंकिंग आफ ट्यूबवैल्ल के लिए लोन मिलता है ऐ, पोल्ट्री के लिए लोन मिलता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि देहात में काम करने वाले लोगों के लिए यह लोन मिलते हैं । इसी तरह पंजाब में भी लोन मिलता है। पंजाब में 35 हजार लोन तक स्टैम्प ड्रियूटी व रजिस्टेरशन फीस नहीं देनी पड़ती लेकिन हरियाणा के अन्दर ऐग्रीकल्चर पर डिपैड करने वाले लोगों पर, फार्मर पर जो सिकिंग आफ ट्यूबवैल के लिए, डेरी डिवैल्पमैंट के लिए या दूसरे धंधों के लिए जो अलाईड एक्टि– विटीज होती हैं, उनके लिए जब वह लोन लेता ऐ तो उसको पहले जमीन की फर्द लेनी पड़ती है और फर्द लेने के वाद वह बैंक की किसी एजेसी के पास जाता है उसरे बाद डेढ परसैन्ट स्टैम्प डियूटी और एक परसैन्ट रैजिस्टेरशन पर खर्च करने के बाद वह जमीन की रजिस्टेरशन करवाता है और फिर तहसीलदार के दरबार में दाखिल होता है । तहसील दार उससे चन्दा लेकर उसकी रजिस्ट्रेशन करता है तब कहीं जाकर के लोन मिलता है लेकिन इसके मुकाबले में पंजाब में 35 हजार तक लोन लेने वाला जमीदार, जिसने सिंकिंग आफ ट्यूबवैल के लिए, डेरी डिवैल्पमैंट के लिए या किसी दूसरे काम के लिए लोन लेना है तो न उसे जमीन की रजिस्टेरशन करवानी पड़ती है, न पटवारी

के पास नाना पड़ता है न तहसीलदार के पास जाना पड़ता हैऔर न रजिस्टेरशन और स्टैम्प डयूटी देनी पडती है । तो सीकर साहब, हरियाणा में, एक तरफ हम कहते हैं कि हम देहाती मे रीजनल इम्बैलैसिज खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन को दबा रहे हैं । यह कहां तक उचित है? स्पीकर साहव, जो लोग शहरों में रहते हैं, वे इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोटन इंडस्ट्री वगैरा लगाने के लिए एक लिमिट बनवा लेते हैं, अपने स्टोर को दिखा कर बैंक मे लिमिट बनवा लेते हैं और उस लिमिट को दिखाकर कर्ज ले लेते हैं जबकि देहातों मैं यह फैसिलिटी नहीं है स्पीकर साहब, रीजनल इम्बैलैसिज को खत्म करने का सरकार ने तहैया किया हुआ है, इसके साथ ही रूरल इम्बेलैसिज को भी दूर किया जाए ।

क्योंकि अब डेरी डिवैल्पमैंट पर बड़ा जोर दे रखा है और यह सोर्स आफ इनकम का एक साधन भी है । जो लैडलेस लोग हैं और थोड़ी जमीन वाले किसान है, वे दो भैसें रखकर, चार भैंसे रखकर या पांच भैंसे रखकर अपना गुजारा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं । लेकिन इसमें भी ज्यादती है । अगर पांच भैसें लें तो पहले तो जमीन का रजिस्ट्रेशन करानी पडेगी, फिर उसके बाद जब लोन मिल जाए दस हजारे का या पन्द्रह हजार का, तो डेढ परसेन्ट स्टैम्प डयूटी देनी पड़ती है । और एक परसैन्ट रजिस्ट्री पर लग जाता है । फिर उसके बाद भैसें जो ली हैं, उन पर ठप्पे लगवाने पड़ते हैं । स्पीकर साहव, खागड झोटे के दागग लगाने वाली बात तो हमने सुनी थी लेकिन दुधारू

पशुओ को दाग लगाने वाली बात हमने आज तक नहीं सुनी थी । इससे तो जो इन पशुओं को रखता है, उसकी मान मर्यादा को भी ठेस पहुंचते।' है । एक दफा एक गांव में मैं गया । मैंने उन लोगों से कहा कि डेरी डिवैल्पमैंट के लिए गवर्नमैंट बड़े पैसे दे रही है, इस बात को वह वड़ा एनकरेज कर रही है कि दुधारू पशु रख कर लोग क्यने जराय मुआस को बढ़ाएं लोग क्यने पांव पर खड़े हो जाएं और दूध को दूसरी जगह दिय) जाए । इस पर एक बूढ़े आदमी' ने कहा कि मेरे दादा ने कहा था कि खानदान के दाग न लगने देना अब आप बताओ कि मैं भैसों को दाग लगवाकर कैसे रखूं? अगर मैं डेरी डिवैल्पमैंट स्कीम के तहत पैसे लेकर चार भैंसें लूंगा तो वे दाग लगाएंगे । (विध्न) दाग लगाते ही दूध को भी थोड़ी ठेस पहुचती है क्योंकि पशु सुकडता है और वह भी दुःख मनाता है । खागड झोटे तो बाहर खुले में चरते हैं, उनको फाटक में नहीं रोका जाता इसलिए उन पर दाग का कोई असर नही पडता । तो दुधारु पशु के ऊपर यह जो दाग लगाते हैं, यह वड़े नुक्स वाली बात है । इस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । एक बात मेरी समझ में नहीं आती । मान लो दस हजार के कर्जे के साथ किसी ने चार भैंसे ले लीं या 6 भैसें ले ली और पेमैंट भी अदा कर दी लेकिन उस पेमैंट के अदा करने के बाद भी निशान यों का यों ही रहता है क्योंकि न तो वह भैंस को बेच सकता हैं और न ही कोई खरीदता है क्योंकि खरीदने वाला कहेगा कि दाग लगी भैंसें हैं । उसे डर होता है कि वे सरकार के कर्जे को भैस हैं ओर यदि ये उसने खरीद लीं तो पकडी जाएंगी

। तो इस तरफ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि दुधारु पशुओं के दाग न लगाए जाएं वैसे यह स्कीम तो बड़ी अच्छी है । इससे छोटे किसानों को ओर गरीब आदमी को बड़ा फायदा पहुंचा है । मैंने अध्यक्ष महोदय एक सवाल के जरिए पूछा था कि एक से पांच किल्ले तक जमीन वाले किसान कितने हैं और उसके जवाब में मुझे वताया गया था कि ऐसे किसान तेरह लाख हैं । तो इस स्कीम से 13 लाख ऐसे लोगों को और 16 लाख हरिजनों को यह सुविधा नहीं मिल सकती है इस सम्बन्ध मैं, स्पीकर साहव, मुझे एक बात और याद आई इस मैं इम्बेलैसिज भी है । अर्बन एरिया मे रेट आफ इंट्रैस्ट अढ़ाई ओर तीन परसैट है लेकिन रूरल एरिया में रेट आफ इंट्रेस्ट आठ परसैट से लेकर साढ़े ग्यारह परसैंट तक है । यदि ये सचमुच ही उन लोगों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहतेहैं ओर उनकी मदद करना चाहते है तो लाजमी तौर पर उनका रेट आफ इंट्रेस्ट कम होना चाहिए । इसकी थोड़ी सी डिटेल्ज भी, स्पीकर साहव, मैं आप को बता दु एक से लेकर पांच एर कड़ तक की भूमि वाला किसान अगर दो हजार रुपये तक लोन. ले तो उस को साढ़े आठ परसैंट रेट आफ इट्ररैस्ट देना पड़ता है इसी तरह से पांच एकड़ जमीन वाला किसान अगर दो से लेकर पांच हजार रुपये तक का लोन ले तो उसे साढे नौ परसैटरेट आफ इंट्रैस्ट देना पड़ता है । यदि पांच से दस एकड जमीन वाला किसान लोन लेता है तो उस को ग्यारह परसैट रेट आफ इंटैरस्ट देना पड़ता है । मगर दूसरी तरफ स्पीकर साहब, शहर में रहने वाले लोग यदि इंडस्ट्री लगाने के लिए 25 हजार

रुपये तक का लोन लेते हैं तो वह उन्हें अढाई और तीन परसैंट के रेट आफ इट्रैस्ट पर मिलता है. यह डिसपैरिटी दर होनी चाहिये इस डिसपैरिटी का दूर होना मैं इसलिए उचित समझता हूं क्योंकि हमारे कृषि मंत्री देहात के रहने वाले कब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहव भी देहात के रहने वाले हैं और इस सरकार ने इम्बैलैसिज को दूर कस्म का फैसला किया हुआ है जव ये रीजनल इम्बैलैसिज का दूर करने पर आमादा है तो इन्हें रूरल और अब में एरिया के अन्दर जो इम्बैलैस है, इसे भी दूर कर देना चाहिए आज लोगों को पता नहीं है कि देहात में और शहर में रेट आफ इंट्रैस्ट में क्या फर्क है । मालूम होने पर लोगों को दुख होता है स्पीकर साहव, लोन के प्रोसैस मे भी बड़ी भारी दिक्कत है । आज देहात का आदमी जब लोन लेता है तो उसको दो–तीन चीजों का सामना करना पड़ता है । रैवेन्यू मिनिस्टर साहब, इस समय बैठे नहीं है, वरना बहुत अच्छा होता । खैर, दूसरे मिनिस्टर साहबान मेरी बात उनको बता देंगे 14 लाख के करीब पास–बुक्स किसानों की बनने थी । इनमें से ह लाख के करीब तो बन चुकी है लेकिन आठ लाख के करीब अभी बाकी हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जव पास–बुक्स बन गई है तो अव भी पटवारी का दरवाजा बार–वार खटखटाने की क्या जरूरत है? जब किसान का पास पास–बुक है तो जब कभी वह डेरी डिवैल्पमैंट का लोन लेना चाहे पोल्टरी फार्म का लोन लेना चाहे, अलाईड ऐक्टिविटीज के लिए लोन लेना चाहे, उस पास बुक से ही काम बन जाना चाहिए उसमें ही सारे कर्जाजात अन्दराज हो जाने चाहिएं । वह सीधा बैक के

मैनेजर के पास जाए, कोआप्रेटिव बैक के एजेंट के पास जाए और उन्हे नम्बर खसराजात वाली पास बुक दिखा दे इसी से उसको लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए और उस लोन की ऐनट्री पास बुक में हो जानी चाहिए । फिर, स्पीकर साहब, मँ यह समझता हूं कि हमारे हरियाणा में भी ऐग्रीकल्चरल फील्ड में किसान को 35 हजार तक लोन लेने वाले फामर को स्टैम्प डियूटी और रजिस्ट्रेशन फी आदि को छूट होनी चाहिए क्योकि इस तरह की छूट पंजाब में रखी है ।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल) : स्पीकर साहव, स्टैम्प ड़ियूटी और रजिस्टरेशन फी छोड़ने का फैसला आज हमने कर दिया है

श्री अमर सिंह : फिर तो बहुत अच्छा किया । बहुत–बहुत धन्यवाद । स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर पर गुजारा करने वाले लोग इंग्लैड में चार– परसैंट है और अमेरिका में केवल अप्लाई परसैंट है मैंने एक पैम्फलैट में पडा है । कितनी हैरानी की बात है कि जो मुल्क सा री दुनिया को अनाज सप्लाई करता है, वहां केवल अढ़ाई परसैंट लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर छैं हमारी तो 88 परसैंट पापुलेशन ऐग्रीकल्चर पर डिपैंड करती है इसीलए ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को सरकार को ज्यादा सुविधाए देनी ही पड़ेगी यह ठीक हूँ कि हमरि पर–एकड़ ईल्ड बढ़ी है क्योंकि इरीगेगन फैमिलिटीज हमें ज्यादा मिली हैं लेकिन इनको अन्त्रार और ज्यादा नहीं बढायगे तो आगे तरक्की नहीं होगी वैस्टर्न जमूना कैनरल का

वाटर रेट जो है वह 1.9 परसैट पर थाउजैंड एकड़ है आदमी तरह भाखडा का 2.4 परसैट है बहुत पुराने जमाने में जब पानी .अधि क होता था और डिमांड बहुत कम होती थी, उस वक्त के ये टू मुकरर्र किए हुए है । इन रेटस को भी रिवाइज कर दिया जाये ताकि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक पानी ले सकें । मेरी कस्टीच्यूएन्सी स्पीकर साहब टेल पर वाक्या है । (विघ्न) इस बारे में भी स्पीकर साहब मैं अर्ज कर दूं । भिवानी डिस्ट्रिक्ट वनने पर बवानीखेड़ा भी तहसील बन गई है और इस तहसील में स्पीकर साहब, आपकी कंस्टीच्यूएंसीं के कुछ गाव भी शामिल हो गए पैं । अब उम्मीद है कि जिन गांवो को पहले सुविधा नहीं मिलती' थी, उनको भिवानी डिस्ट्रिकट में शामिल होने से वह सुविधा मिल जाएगी स्पीकर साहब, बवानी–खेडा के दस– बारह मील के एरिया में न नहर का पानी है और न. ही कुओं का पानी है क्ये 1ाऐंइउ ट्यूववैल्ज मैं खारी पानी निकलता है और गवर्नमैंट ने सिकिंग–आफ–ट्यूबवैल के प्रोग्राम के तहत कोई टयूबवैल लगाने के लिए सर्वे नहीं किया है और न ही कोई आगुमेटेशन ट्यूबवैल लगाए हैं जिस तरह से कि दूसरे एरियाज में लगाए थैं । मैं यह समझता हूं कि इरीगेशन की पूरी फैसिलिटीज या सुविधायें जुटाने के लिए प्रवन्ध करना चाहिए क्योकि वहां की भी वही हालत है जैसे लुहारू और भिवानी की है वहां पर सारी फैमेलिटीज जप्ट टाने के त्निए, वहां पर आगुमैन्टेशन ट्यूवैल्ज लगाये जाने चाहिएं । बवानी–खेडा के आस पास के एरिया में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ हूँ

बवानी खेड़ा मैं 16– 17 साल पहले मंडी के प्लाट्स कटे थे लेकिन वहां पर आज तक मंडी नही बन पायी है । कुछ प्लेटफार्म पी ० डब्ल्यू ० डी ० ने जरूर बनवाये है लेकिन प्लेटफार्म ही बने हुए हैं, न वहा पर कोई दुकान बनी है, न इलैक्ट्रीसिटी की, न वाटर की और न ही सीवरेज की फैसिलिटी है । इसका कारण यह है कि वह एरिया प्रोडेक्टिव नहीं है जब एरिया प्रोडेक्टिव होगा तब ही मंडी कामयाब होगी जहां दूसरे एस्ता के लिए ऐग्रीकल्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां इस एरिया में भी खास. तौर पर ध्यान. रखना चाहिए जहां इस एरिया में ऐग्रीकल्चर में तरक्की नही हुई है वहां इस के लिए भी कोशिश करनी चाहिए ।

स्पीकर साहब एक प्वायंट और कहना चाहता हूं यहां पर हाउस में कहा जाता है कि ऐग्रीकल्चर का लोन देने के लिए सव बैक्स को आर्डर है लेकिन वहां तो बैक्स के रेडियम बने हुए हैं और वह रेडियस दस मील का है । वे कहते हैं कि हम तो उसी रेडियस के लोगों को लोन देते हैं । जैसे बवानी खेड़ा है उसमे हांसी का बैक 16 मील के फासले पर है और भिवानी का का बैक 15 मील के फासले पर है । बवानी खेड़ा के लोगों को कोई भी बैक लोन एडवांस नहीं करता है । इसलिए मेरी आपके जरिए गुजारिश है कि बवानी खेडे में भी कोई बैक होना चाहिए। अगर वहां पर बैक नहीं खोला जा सकता है तो वह जो 10 मील का रेडियस रखा हुआ है वह ऐक्सटैड होना चाहिए । अगर कोई

किसान नारनौंद का रहने वाला है तो वह बैंक लोन ले ही नहीं सकता है । जो रेडियस 10 मील का रखा हुआ है यह क् से कम 20 मील का होना चाहिए । उस एरिया के देहातों में रहने वाले किसानों को यह फैसेलिटी मिलनी चाहिए ताकि सब को लाभ हो सके

स्पीकर साहब, जहां मैं एग्रीकल्चर का जिक्र कर रहा हूं वहां इन्डस्ट्री के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूंय इन्डस्ट्री पर, जो कि स्माल स्केल की इन्डस्ट्री हैं उस पर सन् 1974– 75 में बहुत थोड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है । यह सरकार गरीबो के लिए समाजवाद को बात करती है, वह इस तरह से समाजवाद नहीं ला सकती । जिस तरह से हम लैन्डलैस को जमीन नहीं दे सकते । सन् 1953 में सरप्लस लैन्ड के लिए एक्ट बना था और उसके तहत काफी सरप्लस लैन्ड निकाली गयी लेकिन जब सन् 1953 के बाद 30–7–58 तक जो छूट दी थी उसके कारण बहुत सारी जमीन इधर उधर चली गयी । जमीन के बारे में तो मेरे से पहले वाले साथी काफी बोल चुके है । वे कल इस बात पर काफी बोले थे । चौधरी चान्द राम के लिए तो यहां फोबिया का शब्द भी इस्तेमाल किया गया । हाउस में कुछ ऐसा सिलसिला बन गया है और मैं तो यह समझ रहा था कि चन्दा डिमान्ड तो कोई नहीं आ गयी है । उन्होंने कहा कि मैं चन्दे का हिसाब तो रखता हूं । वे भले ही रखते हों । चौधरी चान्द राम ने यह भी कहा कि मुझे पर तो चढ़ावा चढ़ता है । मैं तो यही कहूंगा हरिजन तो जमीन चाहते

हैं । वह जमीन ही के नाम का चढावा है । वह जिस तरीके से चढ़ रहा है, झूठे जमीन' के नारे देकर लोगों को बहकाया जा रहा है । वे कल को जमीन न मिलने पर लाठी भी मारेगे । स्पीकर साहब, मैंने लैन्ड–लाज को काफी स्टडी किया है । मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हरिजनों को भू–मण्डल पर जमीन नहीं मिलेगी । मेरे साथी चौधरी चान्द राम इस बात की पड़ताल अमेरिका या रूस से करके आये हों तो दूसरी बात है कि हरिजनों के लिए चान्द पर प्लाट दिये जा रहे हैं । लैन्ड सीलिंग ऐक्ट बना । इस एक्ट के बनने के बाद रूल्ज पब्लिश होते ही इस ऐक्ट को चौलेन्ज कर दिया गया । अब उसका कब फैसला हो और कब जभीन हरिजनों को अलाट होगी? स्पीकर साहब, आप तो परमानेंट लाइयर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर रहे हैं, आप तो बड़े लीडिंग लाइयर रहे हैं । आपको पता है कि जमीन के कितने उलझे हुए कानून हैं । जब तक लोगों की मनोवृति नहीं बदलेगी, समाजवाद की भावना हमारे अन्दर नहीं पैदा होगी तब तक पिछड़े हुए लोगों को जमीन नहीं मिल सकती है । यह कानून–कानून ही रहेगा । इसकी इम्पलीमैंटेशन में बड़ी दिक्कत है आज अगर हम यह मान कर चले कि हरिजन पिछड़े हुए हैं ओर वाकई ही हमारी उन के साथ हमदर्दी है और वे हमदर्दी के काबिल हैं, तभी उनका कल्याण हो सकता है हमें यह देखना पड़ेगा कि वे जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन को उनके पांव पर खड़ा करना पड़ेगा । उनको सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर ऊपर उठाना होगा । हम उनकी जमीन देने में तो असमर्थ हैं ।

मैं हांसी में जो जलसा 13– 1– 1974 को हुआ की प्रधानता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह जरूर बताना चाहता हूं कि मुझे किन हालात में चौधरी पीर चन्द जी एम ०एल ०ए ० ने और लोगों ने प्रैजीडैन्ट बनाया । उस जलसे में तो पहले ही दो प्रधान बन चुके थे । वहां पर पहले ही स्टेज पर प्रधान के लिए झगड़ा और जूता बज चुका था । एक तो पहले प्रधान चौधरी चिरंजी लाल जी थे जो प्रो. चान्द राम थे ओर दु सरे प्रधान श्री भगीरथ लाल जी दुःखी थे । दोनों राज बहुत जल्दी बदले उन दोनों प्रधानों को आपस में कशमकश हो गयी, झगड़ा बढ़ गया नौबत चोट और मार–पिटाई की आ गयी । पीर चन्द जी जो कि बिजनैसमैन हैं, उन्होने मेरा नाम प्रधान के लिए जलसा में पेश कर दिया । तो इन हालात के अन्दर मुझे प्रैजीडैन्ट बनाया गया । उस दिन तो दोनों तरफ लोगों में इतना जोश था कि पता नहीं कितने लोगों को चोट लगनी थी जहां तक चौधरी चान्द राम जी को चढ़ावा चढ़ने की बात है जोकि उन्होने हाउस में कल कही थी उसको तो वह किस तरह से रोके । इसका हिसाब किस को दें ,जो हिसाब–किताब की बात थी वह उन्होंने कल यहां बता ही दी कि चढ़ावा है और चौधरी चांद राम चढावा है जिसके हिसाब की क्या जरूरत है गुरुद्वारा या मन्दिर में भी कोई चढ़ावा चढ़ें तो उसका भी हिसाब होता है । तो इसका भी हिसाब समाज को देना चाहिये, यही हांसी में जलसे में मांग की गई थी ।

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) : आन ए प्यायंट आफ आर्डर, सर । क्या चौधरी चान्द राम जी गुरूद्वारा या मन्दिर हैं?

श्री अमर सिह : उसकी बिरादरी ने मान रखा है अब हिसाब की बाबत उन्होने स्पीयर ही कर दिया है कि चढ़ावा है । फिर अब चान्द राम जी की क्यों रट लगा रखी है? चौधरी चान्द राम जी बड़े तगड़े हैं, बड़ी तगड़ी स्प्रिट जमीन का नाम लेकर लोगों में भरी है इसी लिए उनको अपनी बिरादरी के हरिजनों की काफी स्पोरट हे । इसी वजह से चन्दा ज्यादा मिला । इतना ज्यादा चढावा किस कारण चडा, इस सिलसिले में यही अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजन को खास तौर पर चमार को जमीनकी ज्यादा भूख है ।

स्पीकर साहब, हांसी में जिस प्रकार से उस दिन जोश था अगर वहां पर पुलिस इन्टरविन नहीं करती तो पता नहीं कितने आदमी मर सकते थे । स्पीकर साहव, मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऐग्रीकल्चर पर डिपैन्ड करने के लिये जमीन की जरूरत है और जमीन का काम लोगों को देने के लिये यह जरूरी है उन्हें जमीन दी जाये । जब तक आप लोगों को जमीन नहीं देते तव तक वह लैडलैस आदमी कर ही क्या सकता है? मेरा सुझाव है कि दस्तकारी की ओर ज्यादा प्रोत्साइन देना चाहिये । दस्तकारी के शोअबे में 1974– 75 के लिये इस बजट में 93 लाख 12 हजार रुपया मुकरर्र किया गया है । मेरे ख्याल में यह रुपया बहुत थोड़ा

है, इसे बढ़ाया जाना चाहिये । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये ह 1 लाख 41 हजार, हैंडलूम इंडस्ट्रीज के लिये 2 लाख 51 हजार, हैंडीकाफ्रट इंडस्ट्रीज के लिये ह लाख 5 हजार, खादी इंडस्ट्रीज के लिये 2 लाख रुपये अदर विलेज इंडस्ट्रीज के लिये 5 लाख रुपया इस बजट में विलेज एण्ड स्माल इंडस्ट्रीज के तहत जो डिमांड दी हुई है, उसमें मांगा गया है । 93 लाख 12 हजार रुपया, जैसे कि मैंने बताया है, छोटे उद्योग धन्धों के लिये, लैडंलैस लोगों को और हरिजन लोगों को रोजगार देने के लिये दे रहे हैं । आप देखिये, हमारी सरकार सिर्फ 93 लाख 12 हजार रुपया लोगों को छोटे–उद्योग धन्धों के लिये देना चाहती है । यह बड़ी थोड़ी रकम है । स्पीकर साहब, अगर देहातों को ऊंचा उठाना है तो उन्हें रोजगार देना होगा । देहात में सिर्फ दो ही तरह को आबादी रहती है । एक तो है ऐग्रीकल्चर लेवर और दूसरी है फार्मर, जो ऐग्रीकल्चर पर डिपैन्ड करते हैं । अव एग्रीकल्चर लेबर और ऐग्रीकल्चरिस्ट, दोनों को लड़ाने से तो काम चलेगा नहीं, अब तो दोनों को काम देने से काम चलेगा । दोनों का काम देकर ही आप खुश रख सकते हैं ताकि देश का उत्पादन भी बढ़ और उन लोगों को रोजगार भी मिले । स्पीकर साहब, आप एक गरीब किसान के घर से ताल्लुक रखते हैं, मुझे यह पता है । आपको भी पता है कि एक गरीब किसान ऑर खास तौर पर देहात में रहने वाला छोटा किसान साल में सिर्फ तीन महीने काम करता है, नौ महीने वह बेकार रहता थैं । जमीन वाला वह किसान भी जो दस–पांच किल्ले जमीन का मालिक है, वह भी बहुत समय

तक बेकार रहता है । उस को भी सरकार ने काम–धन्धा देना चाहिये । जो ऐग्रीकल्चर लेबर उस थोडी जमीन वाले किसान पर डिपैन्ड करता है. वह आज आजादी से काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए कोई काम बै नहीं । इस वजह से वह मजदूर दु:खी है । उसको भी सरकार को काम–धन्धा देना पड़ेगा । मुझे यह कहने में कोई हिचकिहाचट नहीं है कि जमीन देने में तो हम टोटली असमर्थ हैं । लैडलाज को स्टडी करने के बाद मेरी यह राय है कि अब जमीन लोगों को नहीं मिल सकती । जमीन को छोड़ कर दूसरा तरीका दस्तकारी का है जिससे उनको रोजगार दिया जा सकता है । देहात के लिये हम क्या करना चाहते हैं यह सब को मालूम है । स्पीकर साहब मैं जापान को मिसाल देना चाहता हूं । मैं जापान में गया तो नहीं हूं लेकिन जापान और जर्मनी की ऐक्टीवीटिज से यह पता लगता है कि उन्होने बहुत तरक्की की है । जापान और जर्मनी जो सैकण्ड वर्ल्ड–वार में बिल्कुल नैस्तनाबूद हो चुके थे जिनके मकानों की दीवारों की जड़ें बिल्कुल उखड़ चुकी थीं वे लोग आज अपने पांव पर खड़े हैं । उनकी जो पर–कैपिटा इन्कम है वह 1692 और 1798 तक बढ़ी है । यह आप लोग जानते हैं कि उनकी पर–कैपिटा–इन्कम किस तरह से बढी है? इसका केवल एक ही तरीका है । बहां पर भी ऐग्रीकल्चर पर डिपेन्ड करने वाली पापुलेशन काफी है । जापान में यह पापुलेशन 17 प्रतिशत है और हमारे यहां 88 प्रतिशत पापुलेशन ऐग्रीकल्चर पर डिपैन्ड करती है । हमं लोग ज्यादा जमीन पर निर्भर करते हैं और वे लोग ज्यादा दस्तकारी पर निर्भर

करते हैं । उनका आज पर–कैपिटा–इन्कम के लिहाज से दुनिया में पहला नम्बर है । हिन्दुस्तान जो ऐग्रीकल्चर पर डिपैन्ड करता है उसका पर–कैपिटा इन्कम के लिहाज से बहुत लो नम्बर हैं । इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट को देहातों में छोटी–छोटी सोसाइटीज या यूनिट्स लगा कर ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी चाहियें जिनसे लोगों को काम मिल सके । अब जैसे निवार बनाने की फैक्ट्री है जूते वनाने की फैक्ट्री या ऐसी ही कोई दूसरी फैक्ट्री । इन्हें छोटे–छोटे यूनिट्स में आप देहात में लगायें । आपके पास बिजली है और दूसरे कई साधन हैं जिनकी सहायता से आप छोटे –छोटे यूनिट्स लगा सकते हैं । आपको न कोई पोस्ट्स क्रिकेट करनी पड़ेगी और न किसी को बहुत ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी । छोटे–छोटे धन्धों में दो–अढाई सौ रुपये माहवार पर दो–अढाई सौ आदमी काम करने के लिये रखे जायें । अगर इस तरह से देहात के लोगों को ऐम्पलायमैंट दी जायेगी तो इससे उन लोगों को इन्कम बढ़ेगी और देश का भी उत्पादन बढ़ेगा । मेरा सुझाव है कि उनको रा–मैटीरियल गवर्नमैंट की तरफ से सप्ताई किया जाये और उनका जो तैयार किया हुआ माल हो उसकी डिस्पोजल गवर्नमैंट खुद कराये । जिस प्रकार सेसुबह ऐम्पोरियम का एक सवाल था ठीक उसी तरह से सैटंर्ज खोल दिये जाये–डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर और सबडिवीजनल हैडक्वार्टर्ज पर, ताकि इन यूनिट्स में जो प्रोडक्शन हो वह इन सैंटर्ज के जरिये डिस्पोज आफ हो । जोरा–मैटीरियल हो, वह इंस्पैक्टर्ज के जरिये उनको सप्ताई

कियाजाये । इससे जो दो–अढाई तीन लाख आदमी रोडज और नहरों के काम पर दिहाड़ी लेकर काम करते थे और अब काम बन्द होने की वजह से बेकार हो गये हैं, ए क तो उनको काम मिलेगा और दूसरे इससे प्रान्त की प्रोडक्शन बढ़ेगी । (घंटी) स्पीकर साहब अभी तो मैं केवल दो–तीन डिमान्डज पर ही बोल पाया हूं मुझे कुछ और टाईम मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए काफी टाईम हो गया– अब आप वाईन्ड–अप कीजिये ।

श्री अमर सिह : स्पीकर साहब मैं जल्दी–जल्दी बोलूंगा मुझे थोड़ा सा टाईम और मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है सिर्फ पांच मिनट और ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब अब मैं रोड्ज के वारे में कुछ कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब रोड्ज के लिये खर्च करने के बारे में भी कुछ पैसे का हाउस सरकार को अख्तियार दे रहा है । मेरी इसके बारे में एक गुजारिश है । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि सड़कें प्रदेश में बनी हैं । सड़कों में माल कैसा लगा है इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जसा हमारा मौरल है और जैसे हम सभाज के अन्दर रहते हैं वैसा ही होगा । जो यह कहा गया है कि 80 प्रतिशत गांवों को सड़कों से कनैक्ट कर दिया गया है इसमें कोई दो राय नहीं है । मैं सरकार का ध्यान अपनी कांस्टीच्यूऐंसी की उन दो –तीन सड़कों

की तरफ दिलाना चाहता हूं जो अधूरी पड़ी हैं । जहां पर सिर्फ डेढ–दो मील का एरिया ऐसा है जो बनना बाकी है । वहां पर मैटीरियल पड़ा हुआ है और अर्थ–वर्क होना अभी बाकी है लेकिन अभी तक वे सड़कें बनी नहीं है । इसी तरह की एक सड़क हिसार से लोहारू वाया हरीता–मंगाली है वह बना दी जाये तो लोगों को आसानी हो जायेगी । हरीता के पास से वी० ऐन० चक्रवर्ती नहर गुजरती है जो कम्पलीट हो चुकी है । वह नहर मेरी कास्टीचूऐंसी से गुजरती है और उस नहर को बने एक साल हो गया है ? वहां पर डेढ–दो मील का जो टुकड़ा हरीता के पास है वह अब तक भी नहीं बना है जिस की वजह से लोहारू जाने वाले लोगों को पहले भिवानी जाना पड़ता है तव वे लोहारू जाते हैं । अगर यह हरीते के पास का टोटा पूरा कर दिया जाये तो 25 मील का सफर कम हो जाता है इसलिये इसे जल्दी से जल्दी बनाया जाये । स्पीकर साहब मेरी कास्टीचूऐसी मे तीन तहसीलें आती हैं हांसी तहसील, हिसार तहसील और बवानी खेड़ा । मेरी कास्टीचूऐसी में तहसील हिसार के चार–पांच गांव तहसील हांसी के दो गांव और बाकी तहसील बवानी खेड़े के गांव पड़ते हैं अगर रावत खेड़ा से जो हिसार तहसील में लगता है सबसे इन्टीरियर में है और चौधरी भजन लाल जी की कास्टीचूऐंसी बिल्कुल अटैच्ड है कोई आदमी बवानी खेड़ा आये तो उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है पहले वह हिसार जाता है फिर हांसी जाता है तब कहीं वह बवानी खेड़ा आ पाता है । मेरी अर्ज यह है कि रावत खेडा टू बवानी खेड़ा को वाया तलवन्डी, रूक्का तलवण्डी, बादशाहपुर बाढे

ब्राह्मणान टू बालावास मिलाया जाये बालावास टू बाढ़ ब्राह्मणान के बीच जो दो–अढाई मील का टुकड़ा है और भुरटाना टू बवानी खेड़ा के बीच जो साढ़े तीन मील का टुकड़ा है इसको बनाने से यहां के लोगों को जो बेकार में 40– 50 मील का सफर ज्यादा करना पड़ता है. वह नहीं करना पड़ेगा । अगर वहां का कोई आदमी तहसील में तारीख भूगतने के लिये बवानी खेड़ा पहुंच जाये तो वह शाम को अपने घर नही पहुंच सकता वह अपने घर अगले दिन पहुंचता है । अगर ये दोनों लिंक बालावास–टू–बाढे ब्राह्मणान गान और भूरटाना–टू–बवानी खेड़ा बना दिए जायें तो लोगों का 50 मील का सफर कम हो जाता है ।

अब मैं वाटर–सप्लाई स्वामि के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ । यह ठीक है कि मई 1954 से 1968 तक 203 गांव कोपीने का पानी मिला है और मई 1968 से अगस्त 1973 तक 436 गांवों को पीने का पानी मिला है । यह टैन्टेटिव प्रोग्रैस तो है लेकिन उतनी प्रोग्रैस नहीं जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिये थी । आप जानते हैं कि पीने का पानी मुहैय्या होना निहायत ही जरूरी है । जहां पर खारा पानी है वहां पर मीठा पानी अवेलेबल होना चाहिये आप को पता है, पानी के बिना आदमी बहुत देर तक जिन्दा नहीं रह सकता और जिन्दा रहने के लिए दो ही लाजमी चीजें है हवा और पानी । मेरा कहने का मतलब यह है कि पानी का मिलना हर इन्सान के लिए निहायत जरूरी है । एक मेरे हल्के में सिहाड़वा वाटर सप्लाई स्कीम है । मेरी रिक्वैस्ट यह है कि इस स्कीम में

बाढे–जाटांन, बाढे ब्राह्मणान, और हरीता गांवों को भी इन्कल्यूड कर लिया जाये । इसी तरह से आठ गांवों की नलवा वाटर सप्लाई स्कीम है लेकिन सिर्फ दो गांव, नलवा और वालावास को पानी मिल रहा है । बाकी जो गांव हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है वे हैं कंवारी, घमाना, भोजराज, गुंजार जहां पर कि पाईप लाईन बिछी हुई है, सिर्फ वाटर कनैक्शन देना है । इसी तरह पपोसा, जमालपुर और बड़सी को वाटर सप्ताई स्कीम अधूरी पड़ी है उनको भी मुकम्मल करवाया जाए । इन स्कीमों को सीमेन्ट का नाम लेकर या कोई दूसरा बहाना लेकर अधूरा छोड़ा हुआ है । मेरी प्रार्थना है कि इन को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ।

स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकर्बड क्लासिज के पिछड़ेपन और गरीबी हटाने की बात है उस के लिए पेज 23 पर 1974–75 के बजट में चालीस लाख रुपया हरिजनों को कर्ज देते के लिए रखा है हरियाणा के अन्दर हरिजनों की पापु– सेशन 16 लाख है और उनमें मुझे और चौधरी चांद राम को भी शामिल कर लिया जाए तो ढ़ाई रुपया फी हरिजन के हिस्से में आता है । स्पीकर साहब, ढाई रुपये में तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता इतनी कीमतें वड़ गई है मेरी यह गुजारिश है कि यह चालीस लाख रुपया बहुत कम है स्पीकर साहब, एक और ज्यादती की बात है कि हरिजन कल्याणा निगम ने हरिजनों को लोन देने के लिए 60 लाख 42 हजार 300 रुपए अव तक सैंक्शन किये और जो पैसा डिस्ट्रिब्यूट

किया गया वह है 31 लाख 37 हजार तीन सौ । जिस हरिजन को रुपया सैशन होता है स्पीकर साहब, उससे 15 रुपए के स्टाम–पेपर पर सिक्योरिटी बांड भरवाते हैं और उस बांड के बाद पटवारी से तसदीक करवाना जरूरी है, तब जाकर लोन मिल सकता है । आजकल के जमाने में पटवारी भी सौ का नोट लिए बगैर तसदीक नहीं करता पहला जमाना तो ऐसा था कि एक दूध के लोटे में तसदीक करदेता था, आज तो वह सौ का नोट मांगता है । पटवारी हरिजन की तसदीक नहीं करता क्योंकि उसकी जायदाद नहीं होती, उसकी जमीन नहीं हीती, कोई प्रापर्टी नही होती, सिर्फ मकान होता है उस की तसदीक नहीं करता

श्री अध्यक्ष : आपने काफी टाईम ले लिया है अब आप खत्म कीजिए ।

श्री अमर सिंह : बस जी एक मिनट और चाहिए

श्री अध्यक्ष : एक–एक मिनट करते करने आपने 40 मिनट ले लिए हैं

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब,मैं कह रहा था कि हरिजनों को रुपया सैक्शन भी हो जाता है लेकिन वह लोन नहीं ले पाता क्योंकि पटवारी की तसदीक के बिना उसे लोन नहीं मिल सकता क्योंकि शर्तें गल्त और तंग करने के लिए लगा रखी हैं, इन पर विचार करना चाहिए । स्पीकर साहब, हम यह वजट और डिमान्ड्ज पास करने जा रहे हैं, यह ठीक है कि हालात पहले से

अच्छे बने हैं (व्यवधान) अव मैं एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो पैसा हम पास करने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे ढग से खर्च करना चाहिए और बचत करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपने काफी टाईम ले लिया है अव खत्म कीजिए

श्री अमर सिंह : अच्छा जी, मैं खत्म करता हूं ।

समाज कल्याण एवं कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) : स्पीकर साहब, कल और परसों बजट के ऊपर बहस हुई और आज डिमांड्ज के ऊपर सदन में कुछ चर्चा हुई । मैं तो अपना ज्यादा समय अपने महकमे के बारे में बोलना चाहूंगा और वह डिमांड नम्बर 5, डिमांड नंबर 13 और डिमांड नंबर 14 हैं । स्पीकर साहव कल बजट पर बोलते हुए इस सदन में एक मैंबर चौधरी चांद राम ने यह जिक्र किया कि यहां पर कुछ चीजें अफसरों के नाम से चला रखी हैं । स्पीकर साहब ऐसी प्रथा पहले भी रही है इनके जमाने में भी रही और कई जगह तो इन्होने अपने नाम से भी कुछ चला रखी हैं और दूसरी बात पता नही

चौधरी चांद राम : आन ए प्याथंट आफ आर्डर स्पीकर साहब ? अभी इन्हें एक दो मिनट ही बोलते हुए हैं और शुरू में ही ..... जैसे शब्द कहे है पता नही ये पालिंयामैंटरी हैं या सद्भावना के अनुरूप हैं ।

Shri Shyam Chand : Mr. Speaker, Governor is a fine and visible link between the State and the Centre. तो इस तरह के जो अनडिगनीफाईड शब्दो का इस्तेमाल हो मेरे ख्याल में उनको ज्यादा से ज्यादा कन्डैम किया जाना चाहिए । ऐक्साईड ऐंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के बारे में पता नहीं क्या कहना चाहते थे

Mr. Speaker : The names of persons in high authority sholud not be dragged in the debate,

Chaudhri Partap Singh Daulta : And that office cannot be discussed at all

श्री श्याम चन्द : स्पीकर स इस महकमे ने पिछले डेढ–दो साल में इतना काम किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । आप भी इस महकमे के इन्चार्ज रहे हैं और आपको एक चीज का पता है कि कितनी मेहनत के बाद हम क्लैक्शन करते हैं । जब मेरे पास यह महकमा आया उस वक इनकम 38 करोड़ रुपए थी और लास्ट ईयर, इतनी ड्राउट कडीशन्ज, थी बिजली की कमी थी लोगों की परचेजिंग पावर भी काफी कम थी उसके बावजूद भी हमने सेल्ज टैक्स के स्ट्रक्चर को रैशनेलाईज किया । सारे लूपहोल्ज को दूर किया और महकमे ने इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया कि हमारा जो रैवैन्यू 38 करोड़ था वह 49 करोड़ हो गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बजट में जो फिर्ग्ज दी हैं, उनसे भी ज्यादा रैवैन्यू यानी 60 करोड़ से भी ज्यादा इस साल ही जाएगा । कल जिक्र किया गया कि शराब की नदियां बहा दीं । स्पीकर साहब, यह एक स्टेट का सवाल नहीं ।

विधान सभा में एक क्वैश्चन का जवाब देते हुए मैंने दो बार आनरेबल मैंबर को बताया कि जब तक नेबरिंग स्टेटस प्रोहिबिशन में यकीन नहीं करती तब तक एक स्टेट प्रोहिबिशन नहीं कर सकती । अगर कोई स्टेट कम्पलीट प्रोहिबिशन करती है तो उसे कुछ टाईम के बाद पिछली पोजीशन पर आना पड़ेगा । स्पीकर साहव आपने देखा होगा कि तमिलनाडू में और महाराष्ट्र में प्रोहिबिशन लागू की गई लेकिन बाद में वहां देखा गया कि इलिसिट डिस्टीलेशन के इतने केसिज प्रोहिबिशन से पहले नहीं थे जितने कि प्रोहिबिशन लागू होने के बाद हुए । स्पीकर साहब, आपने देखा होगा कि जब महेंद्रगढ में प्रोहिबिशन लागू की गई तो उससे पहले सारी स्टेट में इलिसिट डिस्टीलीशन के 150 केसिज थे लेकिन जब यह प्रोहिबिशन लागु हुई तो एक ही जिले में 751 केसिज पुलिस डिपाटंमैंट को और कोर्ट्स को डील करने पड़े और काफी रैवैन्यू का घाटा चा । इस चीज को ध्यान में रखते हुए पिछले साल प्रोहिबिशन काऊसिल की मीटिंग हुई और उसमें जिक्र आया कि प्रोहिबिशन होनी चाहिए या नहीं ।

स्पीकर साहब हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी. स्टेट्स भी हैं जहां पर कि लोग देवी–देवताओ पर शराब चढ़ाते हैं और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान के निर्माता थे उन्होने यह सारा मामला स्टेट्स पर छोडा कि अगर स्टेट चाहे तो प्रोहिबिशन वहां पर लागू करे ।

एक आवाज : आप भी वह देवता हैं?

श्री श्याम चन्द : मैं तो शराब नही पीता. स्मीकर साहब, आपने ऐक्साईज मैनुअल देखा होगा । ऐक्साईज ऐक्ट भी पढा होगा । उसमें यह है कि किसी भी मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है कि वह लाइसंस दे । यह सारी पावर्ज केवल ई०टी० सी० को हैं कि वह जिसे चाहे लाइसंस दे सकता है लेकिन यहां –इस विधान सभा में हमारे दोस्तों ने जिकर किया कि हमने लाईसैस दिए । हमने पूछा कि किन को दिए गए? जो नाम उन्होंने बताए उन्हें हमने वैरीफाई किया और यह पाया किसी के नाम ऐसा कोई लाईसैंस नही है । स्पीकर साहब मै तो यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई मैंबर साहबान इस विधान सभा में कोई बात कहे तो जिम्मेदारी से कहें गैर जिम्मेदाराना बात न करें । इसके बाद स्पीकर साहव इसके आगे मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां पर फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट के बारे में भी जिकर आया और यहां पर कहा गया कि आटा नहीं मिलता । स्पीकर साहब इनको यह नहीं पता कि हुमने दो महीने में कितने ही डिपोज खोल दिए हैं और राशन कार्डज भी चौक करवाए हैं । कई नए भी बनाए हैं और जितने भी बोगस कार्ड थे वह सारे ऐलिमिनेट कर दिए हैं । पिछले दो महीनों में स्पीकर साहब हमने कोई लगभग 250 फेयर प्राईस शॉप्त खाली हैं और हरेक गांव को यह आफर की है कि अगर वे फेयर प्राईस शाप्स अलग रखना चाहते हैं दूसरे गांव के साथ नहीं लगना चाहते तो हम उनको भी डिपोज देंगे और जहां डिपोज पर शार्टेज है–आटे की या किसी और दूसरी खाने वाली चीजें की तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा खाने की चीजें सप्लाई की

जाएंगी ऐसा हमने इंतजाम किया है । स्पीकर साहब आटे के बारे में भी मैं बता दूं । हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि आटा नहीं मिलता । हमारे लिए सैंटर की तरफ से 10 हजार टन गेहू का टारगेट फिक्स किया जाता है और हमारे सारे डिपोज पर दो या तीन हजार टन ही आटा लगता है और बाकी का हमारे स्टोर्ज में पड़ा रहता है लेने वाला कोई नहीं है । हमारे यहां पर यह कहते हैं डिपोज पर आटा ही नहीं मिलता है । स्पीकर साहब, मैं यह बता देना चाहता हूं कि आटा डिपोज पर मिलता है । अगर डिपोज पर आटा नहीं है तो इस की जिम्मेवारी सरकार पर है । अगर कोई डिपोज से ही लेने न आए तो इस में सरकार का कोई कसूर नहीं है । स्पीकर साहब इसके साथ–साथ महकमे ने और भी कदम उठाए हैं । यहां पर कहते हैं कि स्मगलिंग होती है । डी०आई०आर० के अन्तर केसिज रजिस्टर करके जिन लोगो ने बेईमानी की है उनके डिपोज को भी कैंसिल किया गया है और अरस्ट भी किए हैं । अगर कोई मैंबर यह बताए कि फलां डिपो में कोई खराबी है या कोई और तंगी हैं खाने–पीने की चीजों के लिए तो इसके लिए हम वायदा करते हैं कि एक तो डी.आई.आर. के तहत उस पर ऐक्शन लिया जाएगा और दूसरे हम यह कोशिश करेंगे कि हरेक डिपो पर और फेयर प्राईज शाप्स पर खाने–पीने की. चीजों की किसी भी प्रकार की लोगों को कोई तंगी न हो । इससे आगे स्पीकर साहब मैं हरिजन वैलफेयर के बारे पुछ कहना चाहता हूं । मैं तो यह समझता हूं कि इस सरकार ने जो हरिजनों की भलाई के लिए काम किए हैं वह शायद पिछले 25– 30 सालों

में कभी नहीं हुए । पिछले साल जनवरी के महीने में स्पीकर साहब हरियाणा सरकार ने जितनी भी हमारी पब्लिक अल्डरटेकिंग्ज थी जो कि लगभग 20 के करीब हैं उन में रिजरर्वेशन की हैं और यह रिजर्वेशन जितनी अब हुई हैं उतनी कभी भी नहीं हुई थी और दूसरी स्टेट्स में इतनी रिजर्वेशन नहीं है । स्पीकर साहब हरियाणा ही एक ऐसा प्रांत है जिसने इस किस्म की पहल की है । इसी तन्ह से कालेजिज को ही ले लीजिए जैसे मैडीकल कालेज हैं इनमें भी हमने हरिजनों के लिए रिजर्वेशनज रखी है । वहां आज तक हरिजन. बच्चों के लिए रिजर्वेशन नहीं थी । पिछले साल मैंने तीनो यूनिवर्सिटीज के वाईस चान्सलर्ज को इस बारे में लैटर लिखे और उन्होंने राइटिंग मे जवाब दिया कि हम हरिजन बच्चों के लिए 20 प्रतिशत रिजर्वेशन करेंगे । और मैडीकल कालेज में आप जाकर देख लें कि पहले नम्बर पर हरिजन बच्चा है जिसके मार्क्स 45 प्रर्तिशत शत थे और जो नान–हरिजन था वह लास्ट बच्चा था उसके 70 परसैंट मार्क्स हैं । अगर यह चीज पहले होती तो ठीक था पर जो ऑज हरिजनों के ठेकेदार बने बैठे हैं जब इन की गवर्नमैंट थी उस समय सरकर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका पेशा तो सिर्फ यही है कि लोगों को बहकाया जाए । स्पीकर साहब, इतना ही नहीं, इसके साथ– साथ गवर्नमैंट ने वजीफे भी लगाए हैं । पहले तो यह होता था कि बच्चो को जब इम्तिहान हो जाते थे तो वजीफे दिए जाते थे और आए महीने उनको दूसरे के सामने हाथ पसारने पड़ते थे लेकिन इस हमारी सरकार ने वजीफा ऐडवांस ही हरेक कालेजों के प्रिंसिपल्ज के पास

भेज दिया है ताकि वह हर महीने ही स्टूडैन्टस को यह वजीफा दे दे ताकि उनको दूसरे लोगों के आगे हाथ न पसारने पड़े । स्पीकर साहब, इसके साथ–साथ हरिजन कल्याण निगम वनाया गया है । इस चीज को मैंने पहले बताया था कि हम उसके तहत फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं ताकि वहां पर जो गरीब हरिजन हैं, उनको रो जगार मिल सके जैसा कि चौधरी अमर सिंह ने बताया कि हरेक हरिजन को जमीन मिल सकती थी, स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि 1963 में, जब कि इन लोगों के पास पावर्ज थी, उस वक्त जमीन हरिजनों को मिल सकती थी । आज इतनी सरपलस जमीन नहीं है कि हरेक हरिजन को दिलाई जाए । अगर वे चाहते तो उस वक्त मिल सकती थी लेकिन उस वक्त इस तरफ कोई ध्यान नहींदिया गया । स्पीकर साहब, इस विधान सभा के मैंबरो की एक कमेटी पार्लियामैंट्री कमेटी पैटर्न पर बनाई गई है और इस कमेटी का काम है कि जहां पर गवर्न– मैंट को पालिसी की इम्पलीमैटेशन में कोई कभी है तो सरकार को उस बारे में सुझाव दे और यह भी सुझाव दे कि हरिजनो के भले के लिए सरकार को क्या काम करने चाहिए । इतना कुछ काम होने के बावजूद भी हमारे जो इस विधान सभा के माननीय सदस्य, चौधरी चांदराम जी हैं, उनको यह फोबिया हुआ हैकि अगर ऐसे ही हरिजनों की भलाई के लिए सरकार काम करती रही तो मेरे को कोई गांव में नही घुसने देगा । इन से पूछें कि यह काम तो पहले भी हो सकते थे, उस वरक भी हो सकते थे जबकि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर थे लेकिन उस वक्त इस ओर कोई

ध्यान नहीं दिया गया और न ही उनकी तरफ से कोई इस बारे में उत्तर होता था । स्पीकर साहब, एक अनफार्चुनेट बात हुईथी । मैंने भी और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी लोगों से कहा कि आप लोगों को जमीन से हम तव तक अविक्ट नहीं कराएंगे जब तक कि आपको कोई परमानैन्ट जमीन न दे देंगे । लेकिन इसके बावजूद भी कुछ आदमियों का यह धन्धा था कि किस तरीके से हरिजनों को बहकाया जा सकता है, किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए और किस तरीके से चन्दा इकट्ठा किया जाए । जितना भी चन्दा इकट्ठा करवाते हैं, उसके लिए अपने एजेन्टों को छोड़ा हुआ है और फिर उस चन्दे में से 25 परसेंट वे लेते हैं 75 परसैन्ट यह लेते हैं । और हरिजनों को फिर बहकाते हैं कि जो चन्दा देंगे उन्हे जमीन देंगे । चन्दा लेने के लिए खुद अन्दर नहीं जाते (विष्य)

15.00 बजे

चौधरी चांद राम रू स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है । मैं आपका ध्यान रूल्ज की धारा 100 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसके पार्ट 8 में लिखा है :

"A Member while speaking shall not make a personal charge against a member."

मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसी बातें कही जाएंगी जो वह मैंबर जिसके खिलाफ चार्जिज लगाए जाते हैं, वह पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिए समय मांगेगा ।

तो इससे कोई फायदा नहीं है । मैंने अपनी स्पीच में किसी पर भी चार्जिज नही लगाए । आप बेशक डिबेट निकलवा कर देख लें ।

Mr. Speaker : Order please. The rule is clear that no personal charge can be made. But you had introduced an irrelevant matter in the House while speaking. Had you not introduced this matter, the debate would have gone on the right track.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैंने किसी के खिलाफ कोई पर्सनल चार्ज नही लगाया अगर कोई बात कही होगी तो वह मजाक में कही होगी । I never any charges against him.

Mr. Speaker : Order Please.

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, मैंने इस बात का जिकर इसलिए किया कि इसका यहां जिक्र आया था और फिर मेरे पास यह डिपार्टमैंट भी है । मैं आपको पोजीशन क्लीयर करना चाहता हूं कि वहां पर जलसा हुआ तो एक वकील साहब को चोट लगी । किसने मारी? यह पुलिस वाले जाने या पोसवाल साहब जानें–जिनके पास यह महकमा है मैं इतना बताना चाहता हूं कि जिस वकील को चोट लगी, उसकी एक ही डिमांड थी कि चन्दे काहिसाब होना चाहिए । वह आदमी संघर्ष समिति का मैंबर था । इन्होने कल अपनी स्पीच में इस चीज को बताना नहीं चाहा, लेकिन मैं बता देता हूं । वह आदमी जेल में भी गया और दूसरे

आदमी भी गए । लेकिन आनरेबल मैंबर का कोई दूर नजदीक का रिश्तेदार, उनके घर से या कोई और संबंधी जेल में नहीं गया क्योंकि इनका काम तो सिर्फ चन्दा इकट्ठा करना था । ये पापुलैरिटी की बात कहते हैं । उसके बारे में पोजीशन यह है कि देहात में हरिजन अनपढ़ होते हैं और जमीन उनके लिए ऐसी चीज है कि उनको इस जमीन का बहकावा देकर उनसे कोई भी काम करवा लो । वे इस चीज है कि पैसा भी लगाते हैं और मुकद्दमे भी लड़ते हैं । और उन दिनों एक और बात चली हुई थी कि हमारे मुख्य मन्त्री जी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाकर ताम्र पत्र बांटते थे पोलिटीकल सफरर्ज को । तो इन्होंने हरिजनों को फिर बहकाया कि अगर तुम जेल में जाओगे तौ तुम्हें भी ये ताम्र पउ दिए जाएंगे और अगर जमीन न मिली तो तुम्हें ग्रांट के रुपये में पैसे मिलेंगे । तो उन दिनों वे लोग बहकाए जाने की वजह से जोश में थे।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जेल के अन्दर की बात तो इन्होंने कह दी कि वहां क्या मिलेगा लेकिन जेल के बाहर क्या मिलेगा यह भी तो बता ई?.. (हंसी).

श्री श्याम चन्द : वह भी बताएंगे । स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा कि मेरे कोई दो मिनिस्टर मिलने आए । लेकिन सच्चाई की बात यह है कि ये कमजोर भी इतने है और कायर भी इतने हैं कि दो पुलिस के आदमी गए थे व्यान लेने के लिए, तो

अगले दिन समझौता कर लिया । इसलिए इनको होम मिनिस्टर मिलने नहीं गए ।

चौधरी चांद राम : चीफ मिनिस्टर का भान था

Mr. Speaker : Order Please. No interruptions.

चौधरी चांद राम : चीफ मिनिस्टर का ब्यान था ।

Mr. Speaker ; No interruptions please.

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, 25 दिसम्बर को अम्बेडकर भवन दिल्ली में जलसा किया । जलसे का ढोंग क्या था? शहीदों को श्रद्धांजलि । पहले इन्होंने जो इश्तहार निकले, उनमें लिखा था कि बूढे–बूढे आदमी आएं और चन्दा लेकर आए स्पीकर साहब अगर 80–8 5 साल का बुढा आदमी सर्दी के कारण जेल में मर जाता है तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है । लेकिन जेल में भी सुविधा दी गई । उसके बारे में इन्होंने खुद माना है कि इन्होंने हरिजनों को कहा कि यहां कच्चे मकानों में बैठे क्या करते हो, चलो जेल मे, वहां पक्के मकान हैं, वहां फ्लश लगे हुए हैं और वहां कम्बल भी मिलेंगे । फिर स्पीकर साहब, आप देखें किये कितने कन्फ्यूज्ड माइंड के हैं । इन्होंने यह भी कहा कि जेल में मालिश के लिए तेल भी मिलेगा (हंसी) लेकिन कोई भाई इनसे यह पुछे कि जो चन्दा इकट्ठा किया गया, क्या उसमें से कुछ पैसे उन परिवारों को भी दिए गए जिनके आदमी जेलों में मरे? पैसे के मामले में इनका यह हिसाब है कि एक दफा जेल में

आ गए, वह बाहर नहीं जा सकता । स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हरिजनो को बहकाया गया । तो जो आदमी चन्दा इकट्ठा करके लोगों को गवर्नमैंट के खिलाफ भडकाए, उसका मकसद यह हो सकता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में आ जाऊंगा । वे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं । 1967 में जब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो मेरे को इन्होंने कांग्रेस में नहीं आने दिया । 1968 के इलैक्शन में ये मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े लेकिन बड़ी मुश्किल से 234 वोटों से जमानत जब्त होने से बची और अगली इलैक्शन हुई तो मेरे खिलाफ दूसरा आदमी खड़ा कर दिया लेकिन फिर भी मैं दस हजार से जीता । मेरी इनसे पुरानी दोस्ती है । जितनी देर मैं मिनिस्टर रहूंगा और चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर रहेंगे उतनी देर तक तो यह कांग्रेस में आ नहीं सकता दूसरा परपज इनका यह है कि यू ०पी० में इलैक्शन आ रहे हैं, किसी तरह से हरिजनो में अपनी इम्पोटैंस कायम करो । जिस तरह से इन्होंने हरियाणा में किया कि वोट हरिजनों से लो और पैसे दूसरे कैंडीडेट से लो, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि आप जहां–जहां भी हरिजनों की वोट बेचेंगे, मैं साए की तरह इनके पीछे रहूंगा और हरिजनों की वोट का सौदा नही होने दूंगा । इसके साथ–साथ मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सर– कार की यह पालिसी है कि हरिजनों को ज्यादासे ज्यादा फैसिलिटी दे । उनको ज्यादा से ज्यादा काम दे और आज भी डी.सीज. कानफ्रैंस में हमारे मुख्य मन्त्री जी ने हर एक डी.सी. को यह कहा है कि जहां पर हरिजन के पास मकान वनाने के लिए जमीन नहीं है,

वहां पर उनके लिए जल्दी से जल्दी जमीन का इन्तजाम करना चाहिए । मैं सदन को दुबारा विश्वास दिलाऊंगा कि जहां भी हरिजन के साथ ज्यादती होगी, वहां सरकार उन आदिमियों के खिलाफ ऐक्शन लेगी । चाहे वह तालीम को कभी के बारे मेंहो, चाहे कोई और दूसरा काम हो, सरकार इन कामों में हरिजनों की मदद करेगी । जो विधान सभा के हरिजन एम०एल०ए ० हैं, चाहे वे अपोजीशन के हैं या इधर के हैं, मैं हर भाई से कहूंगा कि वे अपनी पोजीशन क्लीयर कूर दें । पहले भी यह चर्चा आया कि जो चन्दा इकट्ठा किया गया वह कहां गया? उसकी या तो कारें खरीदी जा रही हैं या कहीं और लगाया जा रहा है । इसलिए मेरे भाई अपनी पोजीशन साफ कर दे कि हम उनके साथ नही है । इन शब्दों के हाथ मैं आपका शुक्रिया अदा करज हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

बहिर्गमन

Chaudhri Chand Ram : On a point of personal explanation, Sir

Mr. Speaker : Chaudhri Phool Chand (Mullana).

Chaudhri Chand Ram Personal explanation, Sir.

Mr. Speaker : Nothing on personal explanation. You introduced the element of Sangarsh Samiti' and he had to reply.

चौधरी चांद राम : मैंने स्पीकर साहब, कोई चन्दे के बारे में भी कहा था क्या?

Mr. Speaker : Order Please. Please resume your seat.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, ... इसलिए मैं ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं ।

(इस समय चौधरी चांद राम हाउस से बाहर चले गए)

अनुदानों के लिए सरकारी मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी फूल चन्द (मुलाना–अनूसूचित जाति) : आदरणीय स्पीकररू साहब, दो दिन से वजट पर बहस चलती रही और आज डिमांड्ज पर चर्चा चल रही है । मैं सभी मांगों पर तो भाग नहीं लेना चाहूंगा लेकिन डिमांड नम्बर 2, 7,10 13, 17 और 24 पर अपने विचार पेश करूंगा । स्पीकर साहब, कल कुछ सदस्यो ने यहां बोलते हुए काफी नुक्ताचीनी की और मैं समझता हूं जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि उन लोगों के पास कोई कंक्रीट सुझाव नहीं होते सिवाए इस बात के कि वे गवर्नमैंट को बिना वजह क्रिटिसाईज करें । जनरल ऐडमिनिस्टेरशन पर बोलते हुए कुछ लोगों न कि कि मिनिस्टर साहेबान लम्बी कारें रखते है और हवाई जहाज पर चढ़ते हैं । मैं समझता हूं कि यह सब उनकी बेकार की बाते थीं । हमने बड़ी कारों के कल फिर्ग्ज

कलैक्ट करवा के देखे तो स्पीकर साहव उससे पता चला कि हरियाणा के वजीरों की बड़ी कारों का खर्चा ऐम्बेसडर कारों से भी कम है यह बात मैं यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं । एक मैंबर ने कहा कि हवाई जहाज खरीदा जा रहा है । मैं उनको बताना चाहता हूं यह कोई फिजूल खर्ची नहीं है हवाई जहाज खरीदने से तो ऐफीशिएंसी बढती है मैं अपने विरोधी दल के भाइयों को इस बात का चौलेजं देता हूं कि जिस भाव पर हरियाणा सरकार ने वह दवाई जहाज खरीदा है उस कीमत पर वे अगर हवाई जहाज खरीदकर दिखा दें तो तो हम उनकी दाद देंगे । हमारी सरकार ने वह हवाई जहाज 9 लाख रुपए के करीब खर्च करके खरीदा है और आज उसकी दुगुनी– कीमत होगी. । इस में एक तो गवर्नमैंट का पैसा कम लगा है और दूसरे ऐफीशिऐसी बहुत बढ़ी है । डिमांड नंबर 10 पर वैसे तो कुल भी मैने जिक्र किया था यहा पब्लिक हैल्प के लिए 13 करोड़ 97 लाख 27 हजार 370 रुपए का प्रोविजन किया गया है इससे जहां पर खारा पानी है वहां पर पीने का मीठा पानी दिया जाएगा । मैं समझता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार, व हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री साहब भागीरथ का अवतार हरियाणा प्रांत में सिद्ध हुए है और इन्होंने जहां लोग पानी को तरसते थे वहां पर पीने का पानी पहुंचाया है । मैं उन से यह निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में लगरछनी, गदौली और बराडा में थी पीने कॉ पानी सप्लाई करने की कृपा करें क्योकि वहा पर लोगों का बहुत तकलीफ पेश आ रही है । अब मैं माग नम्बर 13 पर आता हूं जो कि सोशल वैल्फेयर और

हरिजन कल्याण से सबंध रखती है । मेरे बड़े भाई चौधरी श्याम चन्द जी ने बहुत डिटेल में बताया कि मौजूद। सरकार ने हरिजन भाइयों के लिए क्या–क्या किया है । उन के लिए कर्जे, निगम चौपाले, मकान और स्टाईपैड वगैरा कॉ बहुत सहूलियतें दी है मैं समझता हूं कि यह सभी काफी सैटिसफैक्टरी काम हैं जो हमारी सरकार ने हरिजनो की भलाई के लिए किए हैं । उन्होने जिक्र किया चौधरी चांद राम की संघर्ष समिति का । वह बात तो ठीक है सच हो गई । लेकिन मैं हरिजनॉ की भलाई के बारे में बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार के वक्त मे और जव चौधरी चांद राम मिनिस्टर थे उस वक्त के काम में क्या फर्क है? जहा तक चौधरी चांद राम के पोलिटिकल कैरियर का ताल्लुक है यह तो किसी भाई से भी छिपा हुआ नही है । विरोधी दल के भाई भी जानते है और दूसरे भाई भी जानते है कि वह किस पार्टी से जीत कर आए थे । उस वक्त यह बात सबको मालूम है कि वह काग्रेस पार्टी की तरफ से जीत कर आए थे । लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्योंकि उनको कुसा को भूख थी जब काग्रेस मैजोरिटी में न आई तो वह काग्रेस को छोड्कर विरोधी दल मैं चले गए । सामन दोलता साहब बैठे हैं उनकी सरकार में वह शामिल हुए । लेकिन वहा पर भी उनकी तसल्ली नही हुई । 6– 7 महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का उन्होने आनन्द चखा लेकिन वहां पर स्पीकर साहब उनका मन नहीं लगा । वहा से छोड़कर वह फिर कांग्रेस में शामिल हुए । लेकिन आप हैरान होगे स्पीकर साहब कि जब मिड–टर्म इलैक्शन के लिए टिकटो का मामला आया तो वह सात

मैंबरी कमेटी के मैंबर थे मगर जब उनको टिकट न मिल पाया तो वह फिर काग्रेस पार्टी को छोड़ कर अलग ही गए । तो यह हैं इनका पोलिटीकल कैरियर । वह हमेशा अपनी जाती गर्ज को जमने रखते है । में कहता हूं कि हरिजनो को भलाई करने को बात तो एक तरफ रही अगर वद अपनी जाता भलाई को इसके लिए न्यौछावर कर दें तो हम उसको भी बहुत बडी' बात समक्ष सकते है लेकिन उनसे इस दात की तवक्को हरगिज नहीं की जा सकती । मैं वश पर यह बताना चाहता हुं कि जिस जमाने मे बह वजीर थे उस समय उन्होंने हरिजनों के अन्दर फर्क डालने के लिए इतनी खतरनाक बीमारी का बीज बो दिया था जिसका कि हिसाब नही लगाया जा सकता और मैं समझता हूं कि उसका बदला देने के लिए शायद उनकी आने वाली पुश्तें भी उसका जवाब नहीं दे सकेंगी । इस शख्स ने हरिजनों की क्लास के अन्दर एक डिसटिंक्शन पैदा की कि यह चमार है यह घानक है यह खटीक है और यह फलां है । मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इसके बीच में क्लासिज पैदा वार दी । आज हम देख रहे हैं कि चौधरी अमर सिंह की जमात और है और दूसरों की कोई और है । इसका क्या कारण है? इस का कारण चौधरी चांद राम है । जब वे डिष्टी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होने इस में एकता लाने का ख्याल हीं किया बल्कि उन्होंने हरिजनों के अन्दर भी कास्टीजम की अलग सोसायटी बना कर खड़ी कर दी और आज मुझे समझ नहीं आती कि वह कैसे इस बात का दावा करते हैं कि मैं हरिजनों का हितैषी हूं । मैं उनको यह चेतावनी दिलाना

चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब वे लोगों में बाहर जाएंगे तो दे उनका जूतों के साथ स्वागत करेंगे । हरिजनों को वह जमीन का लालच दे–दे कर बहकाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वे जमीन कहां से देंगे? स्पीकर साहब वह मौका बहुत जल्दी आ रहा है जब कि इन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा । जब यह ताकत में थे तो जो–जो इन्होंने हरिजनों की भलाई के लिए काम किए उस का खुलासा मैं बताता हूं । इन्होने खड़खौदा में लैदर टैनरी चलाई । वहां की सोसायटी के वह चेयरमैन रहे लेकिन आज तक मांगने पर भी उस का हिसाब किताब नहीं दिया और पैसा खा गए । पता नहीं उस में से कितना पैसा खा गए हैं । फिर बीड़ सुनारवाला को–ऑप्रेटिव सोसायटी थी, छुछकवास को–ओंप्रेटिव सोसायटी थी, इन सब में उन्होंने अपने रिश्तेदार भर दिए कोई भाई कोई सास, कोई ससुर, कोई साला और कोई पैसे लेकर शामिल कर लिए ।

आप बेशक देख ले रिश्तेदारी के सिवाये दूसरा कोई आदमी नही भरा है ओर अगर कोई भरा है तो वह भरा है जिससे पैसे लिये होंगे. बिना पैसे के तो आज तक इन्हों ने किसी का काम किया नहीं । चंदा लेना तो इनकी आम बात है और कल वह यह बात स्वयं भी कह रहे थे कि 'चंदा राम' उनको कहते हैं । बात भी ठीक है जो चंदा राम कहते हैं । जो भी आदमी इनके पास जायेगा किसी न किसी बहाने से उससे चंदे की बात जरूर करेंगे और अगर कोई नहीं देता और देने को तैयार होता नजर

नहीं आता तो फिर इन्होंने जो एक परचा चला रखा है उस अखबार के नाम पर ही किसी से दस रुपये लिये बगैर नहीं आने देंगे. वहतो इनका आखिरी' हथियार है । यह लोगों की भलाई की बात क्या सोच सकते हैं जो ऐसी बातें करते हैं? फिर दूसरों पर ऐलीगेशंज लगाते फिरते हैं! हमारे एक मंत्री महोदय पर इल्जाम लगा चे थे और कह चे थे कि माडल टाउन में क्या होता है । मैं इस बात पर फिर आता हूं पहले यह बताना चाहता हूं कि जब यह वजीर थे तो इन्होंने बहादुरगढ़ को इन्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करायी और वहां की एक पार्टी सूरजमल वगैरा दे इनको पैसे भी दे दिये और एक कार भी दे दी और साथ में एक प्लाट भी खरीद कर दे दिया और वह प्लाट इनके नाम पर आज भी है. ।

फिर यह हरिजनों की भलाई के गाने गाते है मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हैं फिर इन्होने जमीन खरीदी । यह डिक्लेयर करवाया कि वह जमीन हरिजन आक्शन में खरीदेंगे । खुद आक्शन में जमीन खरीद ली और मालिक बन गार और आज वह लाखों का आदमी है । मैं पूछता हूं यह सारा कुछ उनके पास कहां से आया? इनका जरिया मुआश क्या है? उन्होंने कभी वकालत नहीं की लेकिन आलीशान कोठी में रहते है कार में चलते हैं । तो यह सारा कुछ कहां से आता है? फिर इनका शरीर भी अच्छा खासा है अंगूरों का जूस पीते हैं लेकिन जिन गरीब हरिजनों की भलाई की वति करते हैं उनको सूखी रोटी नहीं मिलती । फिर यहां खड़े हो कलेम करते हैं कि चांद राम के

कहने पर हरिजन चलते हैं । मैं कहता हूं कि कहीं वाहर जा कर तो देखो कि लोग क्या कहते हैं? इन्होंने हरिजनों की भलाई के नाम पर एक संघर्ष समिति बना कर एक ऐजीटेशन चलाई और उसे चलाने के लिये लोगों को चकमे दिये. बहकावे दिये कि जमीन मिलेगी । हमारे एक भाई साहब ने यहां पर बताया है और भी कई लालच दिये, लेकिन मैं पूछता हूं उन से कि नतीजा क्या निकला? आखिर स्टैड क्या था इनका? सरकार का क्या स्टैड था और इनके इस आंदोलन से कय सरकार का वह स्टैंड बदला, नीति बदली? हमारी सरकार ने जो स्टैंड शुरू में लिया था वह आज है कि जो हरिजन जिस जमीन पर बैठा है उसको तव तक बेदखल नहीं किया जायेगा जब तक कि उसको आल्टरनेटिव जमीन नहीं दी जाती । क्या फायदा हुआ इनकी उस समिति का सिवाये इसके कि गरीब हरिजनों को वहां बहका कर ले गए उनको काम से खोया और पैसे भी उन से ले लिये । वह कहते हैं कि लोग तो उनको पैसे चढ़ाते हैं लेकिन मैं उन से पूछता हूं कि क्या वह कोई मन्दिर गुरुद्वारा या मस्जिद हैं जो उनको लोग पैसे चढ़ाते हैं? उन से बहका कर लालच तरह–तरह के देकर पैसे लिये गये और मैं यहां पर यह इश्तेहार पेश कर सकता हूं जिस में लिखा है हरिजन भाइयो! अपनी भलाई के लिये भारी तादाद में आओ. चंदा लेकर आओ और सीधे ही चांद राम के पास चन्दा लेकर पहुंच जाओ (हंसी) और कहीं न जाओ सीधे पैसे लेकर चांद राम के पास ही जाओ यह है इनका हाल । मुख्य मंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों मे कहा था कि यह सरकार हरिजनों के साथ कोई ज्यादती की बात

नहीं होने देगी और वही स्टैंड अब भी सरकार का है । मैं इस सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ है कि हरिजनों को उन जमीनों से बेदखल न किया जाये जब तक कि उनको आल्टरनेटिव जमीन नहीं दे दी जाती । तो मैं स्पीकर साहब. अब रोहतक वाली बात की तरफ जता हूं । मैं पूछता हूं कि वह बतायें इस हाउस में खड़े हो कर. बहां माडल टाउन में बख्शी ब्रादर्ज के यहां क्या होता था? और जालन्धर में अपने भतीजे की शादी कैसे करवाई । (विघ्न) यहां खेती–बाड़ी के बारे में चौधरी अमर सिंह जी बात कर रहे थे तो मैं अर्ज करता हूं कि खेती –बाडी के लिए जितना पैसा मांगा गया है मै समझता हूं कम है । हरियाणा की 80/85 फीसदी आबादी देहात में रहती है और खेती पर गुजारा करती है इसलिये खेती की तरक्की के लिये ज्यादा प्रयत्न करना चाहिये । आज हमारे मंत्री जी ने अपनी स्पीच में यह बताया भी है कि हरियाणा में पैदावार कुछ कम रही और किस वजह से ऐसा हुआ यह भी उन्होने बताया लेकिन एक बात बताना वह भूल गए कि चांद राम जैसों पर भी इस पैदावार को कम करने

में हाथ था क्योंकि खेती–बाडी करगे वाले जो लोग थे. उनके तो यह बहका कर दिल्ली से गये, खेती की बुआई–कटाई बगैरा को बात ठीक नहीं हुई इस लिये इसका पैदावार पर असर पडा । इस लिये उनकी जिम्मेदारी थी. इस पैदावार को कम करने की आती है । स्पीकर साहब. जो लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं देखते कुछ हैं, बताते कुछ हैं क्या उनका कोई स्टैंड हो सकता है कोई मोरल हो सकता है? मैं कहता हूं शर्म की भी कोई हद होती है । ..... जो इस तरह की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि वह हरिजनों के हितैषी हैं । .... आखिर इतने साल इनको पोलिटिक्स में आये हो गये .... कुछ कस्टस्टिव सुझाव रखें जिनसे इन गरीव हरिजनों की भलाई हो । अब कांग्रेस में आने के लिये भागते हैं लेकिन कांग्रेस को जब जरूरत थी तो नहीं आते थे । मुझे इनकी यह बातें देख कर एक शेर याद आता है ।

‘ ‘भागती फिरती थी दुनिया जब तलक न भागे थे हम

अब की जब नफरत हुई के बेकरार आने को हैं । ‘‘

यह इनका हाल है । स्पीकर साहब, हमें दु:ख होता है ऐसी जतो को देख कर । हमारी सरकार ने यह जो मांगे सदन के सामने पेश की हैं, वह गरीबों की भलाई और राज्य की भलाई के लिये हैं लेकिन हमें ऐसे लोगों से बचना है जो गरीबों को बहकाते हैं । उनसे पैसे लेते हैं मोर सरकार को बदनाम करते हैं । हमारी

प्रधान मंत्री जी ने जो गरीबी हटाओ की बात कही है, यह बजट उस प्रोग्राम के अनुसार ही पेश किया गया है । हमें इस ढंग से चलना हैं, इस ढंग से काम करने है कि जिनसे क्लासलैस सोसायटी बने, गरीबी दूर हो और सब प्रकार से प्रान्त की तरक्की हो । तो स्पीकर साहब, मैं अर्ज करता हूं कि हमारी सरकार ने यह जो बजट पेश किया है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्रैसिव है ।

मैं कुछ अब ट्रांसपोट के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि जब हमारा हरियाणा बना तो हमारा राज्य ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत पीछे था लेकिन आज हम फख के साथ कह सकते हैं कि सारे भारत में हमारी सर्विस बेहतरीन मानी जाती है । ट्रांसपोर्ट को नेशन लाईज करने में देश के अन्दर हम नंबर दो पर हैं । हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस सारे देश में ऐप्रीशियेट की जाती है । आप अपनी बसों में बैठ कर देखें और दूसरे प्रांतों की बसों में भी बैठ कर देखें, आपको सारा पता लग जायेगा । मैं ने तो देखा है और मैं बाहर जाकर बसों में सफर करके देखता हूं तो मुझे हरियाणा की बसें याद आती हैं ।

अब मैं टूरिजम के बारे में भी कुछ जिक्र करना चाहता हूँ । इसमें सिविल ऐवीएशन भी आती है जिसकी तरफ आम आदमी दा ध्यान नहीं जाता है । मैं यह फख की बात समझता हूं कि हरियाणा बनने के वक्त सिविल ऐवीएशन की उड़ानें लगभग दो हजार घंटे की इस प्रांत में थी लेकिन आपको अब यह जान कर

खुशी होगी कि इस वक्त हमारी सिविल ऐवीएशन की उड़ानें 6 700 घंटे की हैं ।

यदि सारी फिर्ग्ज कलंक्ट की जाएं तो हम इस निकर्ष पर पहुंचेंगे कि हरियाणा प्राप्त सिविल ऐवीएशन में भी नम्बर एक पर है । हरियाणा ने तो बहुत से मामलों में पहल की है । सैड रिफार्म में की है बिजली में की है और बहुत से धन्धों में की है । तो स्पीकर साहब, मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आइए, इस प्रान्त को अच्छा बुनाने के लिए, ऐसे सुझाव दें जिससे यह प्रान्त आगे बढे । पीछे न जाए, किसी की टांग न खीचे । .... हिसाब तो वे किसी को देते नहीं, इनसे बचे । गरीब भाइयों से मेरी यह खास अपील है । गरीबो के हितैषी वह नहीं हैं, गरीबों के हितैषी तो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे चौधरी बंसी लाल हैं और हम उनके नुमायदे हैं । हमारा पुरा सहयोग उनको हासिल है । इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं इन डिमांड्ज को स्पोर्ट करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

चौधरी प्रताप सिह दौलता (बेरी) : स्पीकर महोदय, यह जो डिमान्ड्ज हैं, इरीगेशन की ऐग्रीकल्चर को और हरिजनों की, मैं इन पर वोलना चाहता हूं । हरिजनों की डिमांड पर बोले बगैर स्वाद ही नहीं आता । आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले इस बजट के लिए मैं अपने फाइनैस मिनिस्टर साहब को तहदिल से मुबारकबाद देता हूं, इसमें मुझे कोई झिझक नही है । इस बार

दूसरी स्टेटो के बजट तो बाद में आएंगे लेकिन–दूसरे प्रदेशों के पिछले बजटों का मैरे सामने गलास हैं । मैंने चौधरी चान्द राम जी को उस रोज भी कहा था कि मैं बोलूगा और अब मैं डंके की चोट से कहता हूं कि लैड ओनिंग क्लास यानी जमींदार के लिए यह बजट जो हरियाणा गवनमैंट ने पेश किया है, इसके मुकाबले का बजट किसी भी स्टेट में पेश नहीं हुआ । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए) मुझे इससे भी ज्यादा खुशी यह है कि जो बजट के पीछे फिलासिफी है, जिसको श्री बनारसी दास जी ने और श्री गुलाब सिह जी ने अर्ज किया है, उसके लिए मैं उन्हें दुवारा मुबारकवाद देता हूं । उन का कहना यह है कि इलैक्शनों की जो मेरी तकरीरें हुआ करती थीं, उस में मैं कहा करता था कि जमीदार तो देश की रीढ़ को हु डी है । लाला बनारसी दास ने बहुत अच्छे तरीके से घुट किया कि जमीदार हमारी इकोनोमी रीड को हडडी है । अगर वह प्रौसपर है, खुशहाल हैं तो सबलोग खुशहाल हैं ओर अगर वह कमजोर हैं तो सब कमजोर है। यदि भगवान बख्शे, जोर का मीह हो, खूब अनाज पैदा हो और उसका अनाज महंगे भाव बिके तो इससे नाई की भी मौज क्योंकि वह उसको बहुत पैसे देगा, खाती की भी मौज क्योंकि वह उससे चीज लावेगा और बनिए की भी मौज (विघन) वह बांट देगा .... सारे धन को सारी जातियों को क्या वह घर रख सकता है? हमारी इकोनोमी का बेस जमींदार है । जिस बजट का 76 फीसदी जमींदारों के लिए खर्च हो उसके लिए मुबारक न दे लफ्जों में

कंजूसी करें दौलता का तो दिल ऐसा है नही, किसी कंजूस का हो तो होता रहे लेकिन दौलता का नहीं है । चेयरमैन साहब मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहूंगा कि कुछ लोग इतने कमजोर दिल रखे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं मेरा इन अपोजीशन वालों पर दावा तो है नहीं क्योकि इन्होंने इलैक्शन में मेरी डटकर अपोजीशन की थी इस हरद्वारी लाल ने इनके भगवत दयाल ये रात दिन एक किया था लेकिन काग्रेसियो ने मुझे राय दी थी, काग्रेसियो ने मुझे इलैक्शन जीत कर दिये था । इलैक्शन जीतते ही नौ हजार वोट इन्हें मिले थे और नौ हजार इन्होने मुझे दिए थे मैं कैसे कांग्रेसी नहीं हूं? (हंसी) लेने का क्या है? दिमाग से मैं कांग्रेसी हूं जिस्म से मं कांग्रेसी हूं । ये लेने वाले कौन हैं मुझे? मैंयह बात नही समझ सका (विघ्न) चेयरमैन साहब मेरी अर्ज यह है कि रूरल इकोनॉमी के लिए जैसे कि जोशी साहब ने वड़ा राईटलो पुट किया प्राईमरी सैक्शन के लिए जो पैदावार करते हैं उन के लिए जो प्रोवीजन इस बजट में दिया कब वह मूबारिक्बाद का मुस्तहिक है । चेयरमैन साहब बेसिक पैदावार या ले जमींदार करता है या मजदूर करता है जो खानों में उतरता है और वहां से धन लाता है पा जो समुद्र की तह से दौलत इकट्ठी करता है? बाकी आबादी तो एक जगह से दूसरी जग। उस पैदावार को पहुंचाने में लगी रहती है । उसकी एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर को बनाने 1। वह आबादी कारखानों में लगी रहती है । चेयरमैन साहब मै फिर कहता हूं कि लैंड–आर्निंग क्लास के लिए जो अरबों का खर्च किया है अगर उसका क्रैडिट बंसी लाल जी को जाता है

तो दौलता इस बात को डंके की चोट से क्रैडिट देता है, इसमें मैं कोई कंजूसी नहीं बरतता । इतनी दिलेरी का बजट यही लोग पेश कर सकते थे । चांद राम जी को फिक्र था कि 300 करोड़ रुपया कर्ज हो जाएगा और इतना भारी सूद हो जाएगा पर मेरी समझ में यह बात नहीं आती क्योंकि न तो कोई पानी को रोकने जा चा है न ही कोई हमारे बिजली के खम्भों को उठाने जा रह है आने वाले बच्चे जो भुगते सो भुगतते रहेंगे, मैं तो इस राय का हूं कि रूरल इकोनौमी के लिए जो खर्च हुआ, उसके लिए गवर्नर बधाई को मुस्तहिक है यह बात हिस्टरी में जाएगी जो इन्होंने खर्च किया है । (हंसी) चेयरमैन साहब, रूरल इकोनोमी के अलावा एक और चीज है जिसकी गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं जो डिवैल्पमैंट हरियाणा में होती है उसके बारे में अगर कोई आदमी बाहर जाकर यह चीज कहे कि डिवैल्पमैट नहीं हुई तो वह कहने वाला खुद यावा होता है बाहर का कोई भी आदमी ऐसा नही कहता यह ठीक है, श्री अमर सिंह जी ने बड़े अच्छे तरीके से पुट किया जो उन्होंने 1938 के बजट के बारे में कहा मैंने भी यह प्वांयट नोट किया हुआ है उस वक्त मैं लाहौर में था । यूनाइटिड पंजाब का वजट 9 करोड़ 28 लाख का था आज 9 करोड़ 38 लाख का बजट तो वहुत सी कारपोरेशन्ज का देखा जा सकता है टाईम–फैक्टर, टाईम–मार्कड डिवैल्पमैंट के लिए जिम्मेवार है, इससे कोई इकार नहीं कर सकता । मै एक बात चेयरमैन साहब श्री गुलाब सिंह जैन से अर्ज करना चाहता हुं । इन्होंने हाउस में एक बात कहीथी कि जव तक पंजाब इकट्ठा रहा, चौधरी छोटू राम

जी ने जोर लगा लिया और सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त में हमने भी जोर लगा लिया लेकिन डिवैलपमैंट नहीं हुई मगर जब से हरियाणा बना है, बड़ी डिवैल्पमैंट हुई । मैंने उनकी इस आब्जौइक्टिविटी के लिए उनको मुबारकबाद दी लेकिन उन्होने वह रिसीव नही की और वापिस इस बिना पर भेज दी कि इससे यह मालूम होता है कि डिवैल्पमैट तो हो गई परन्तु इसमें बंसी लाल जी का हिस्सा नहीं हुं मेरी इस सम्बन्ध मैं इनसे लौबी में बात हुई थी । अरे भाई मेरे, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरना चाहता, चाहे यह मेरा मूंछों वाला पड़ौसी मुझे कुछ भी कहे? शुरू में जब मैं हाउस में दाखिल हुआ था, मैंने जो पहली तकरीर की थी, उसमें मैंने कहा था कि इस डिवैल्पमैंट में ज्यादा हिस्सा तो उन मेरे जैसे समझदार आदमियो का है जिन्होंने हरियाणा बनाने में पार्लियामैंट में बड़ा भारी जोर लगाया है । अगर उसके बाद किसी को क्रेडिट जाता है 25 परसैट तो वह चीफ मिनिस्टर साहब के डायनेमिजम को जाता है जो कि चौधरी बंसी लाल जी के पास है । जो करैक्ट बात है. उसको शर्मिदा होकर के क्यों छुपाते हो? (विघ्न) अगर कांग्रेस नहीं है तो बेचारा बंसी कहां है? चेयरमैन साहब, मुझे क्योंकि टोक दिया इसलिए मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि मेरा यह यकीन है कि मुल्क इस वक्त तक ही डैमोक्रैटीकली इकट्ठा है जब तक इंदिरा है और कांग्रेस (आर) है । मुझे यह कहते हुए कोई डर नहीं । यह ठीक है कि आज इज्जत पसंद ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं । कल ही मुक्तसर में इकट्ठी हुई । जनसंघ और अकाली पार्टी का क्या मेल

है? एक कहता है कि सिख खतरे मै है एक कहता है हिन्दू खतरे में हैं अकाली जनसंघ के लीडर को कार के पैसे देते हैं । चौधरी चरण सिंह, मेरे रिश्तेदार है, शायद आपको मालूम नहीं है । मेरी बहन वहां व्याह रखी है और मेरी बहन की सगी ननद उनकी वाईफ है । मैं चौधरी चरण सिंह के खिलाफ पार्लियामैंट के हलके में गया अपने कामरेड के लिए और वह कामरेड जीता और मुझे यकीन है कि यदि वह कामरेड फिर खडा होगा तो वह फिर जीतेगा । मुझे इससे कोई गुरेज वही । मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि जब दुनियां भर की इज्जत–पसन्द ताकतें इकट्ठी हो सकती हैं तब दौलता अगर कांग्रेस की हिमायत करता है तो ये अपोजीशन वाले मुझे उलट क्यो समझ लेते हैं? क्या मैं किसी का बिका हुआ हूं? हम तरक्की–पसन्द ताकतें है, सी0 पी0 आई0 है, दूसरी है, इंदिरा हमारी लीडर है । हम इस बात को डंके की चोट से कहते है, कोई छुपाते नही है । Indira is a national leader इन्दिरा तमाम तरक्की–पसन्द लोगों की लीडर है इंदिरा मेरी तो लीडर जरुर है चाहे इनकी हो चाहे न हो । (तालियां) चेयरमैन साहब, बीच में टोका टाकी जनरल प्वांयट बिल्ड करने नहीं देती । ये कांग्रेस में मुझे लें या न ले, मैं कांग्रेस को वोट तो जरुर दूंगा चाहे कोई भी बात हो । कोई मोंका हो, मैं कभी दिल्ली में घुस कर यह नहीं कहने दुगा कि तेरा फूड मिनिस्टर स्मगलिंग करता है या तेरा चीफ मिनिस्टर रप्ट है । मैं दिल्ली की लोबी में. जो मेरा फर्ज है उसको पूरा करूंगा । मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं । यहां पर चीफ मिनिस्टर साहब किसी दिन गुस्से में जाकर कुछ कह ई

तो अलग बात है लेकिन मुझे तो अपनी हैसियत का पता है । मैं तो अपनी स्टेट का, अपने सी० एम ० का, अपनी गवर्नमैट का और अपनी अपोजिशन का भी जो इस गवर्नमैंट का जुज है, बहुत परेज्र करने वाला हूं । ये यू ही विरोधी दल कहते रहते है क्योंकि इम्मैच्योर्ड लड़के इलैक्ट हो गए और वे विरोधी–विरोधो कहते रहते है । विरोधी क्या होता है? (विध्न) यह गलत बात है । Bansi Lal is the Chief Minister of the House. He is as much the Chief Minister of anybody as of this side. These are all our Ministers. Constitution does not recognise any Party. Constitution says that a party which commands majority, a person who commands majority, will form a Government. T That does not say which party? So long as Constitution goes, so long as law goes, this House is one, a Cabinet is our selected Committee and we should have the same approach.

अच्छी बात की बडाई करो और बूरी बात का क्रिटीसिजम करो लेकिन विदहैल्दी अप्रोच । तो मैं अर्ज किए देता हूं कि जहां तक नहरों और बिजली का ताल्लुक है उसके हम प्राउड हैं । वह तो अचीवमंट हु ई ऐ उसका हमें प्राईड है । अफसर की भी यहां बात आई परन्तु मैं तो हाउस में न अफसरों की बड़ाई किया करता हूं और न ही निन्दा करता हूं । ये दोनों बातें ही गलत हैं ।. रही बात ऐग्रीकल्चर महकमे और स्मगलिंग की बात, चेयरमैन साहब, मैं दावे के साथ फिर दोहराता हूं कि इस मामले में सैन्ट्रल हाल में भी कई आदमियों से और जरनेलिस्ट्स से मेरी बातचीत हुई । हरियाणा में इस बार अनाज बहुत कम हुआ । हरियाणा में

स्मगलिंग नहीं हुई, हरियाणा में स्मगलिंग हो नहीं सकती क्योंकि यह बहुत छोटी सी स्टेट है । इस स्टेटस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतना सख्त है कि समगलिंग के लिए कोई गुजाइंश नही है । मैं यह इस वास्ते नहीं कहता कि ऐग्रीकल्चर का इन्चार्ज चौधरी भजन लाल है, जो कि मेरे दोस्त हैं । मेरा दोस्त यहां कौन नहीं है? मेरी तो सारी वजारत ही दोस्त है । मुझे तो कभी यह वहम ही नही हुआ कि मैं वजीर नहीं हूं, पता नहीं इनको कैसे गलतफहमी हो गई? (हंसी) मैं एक बात दावे से कहता हूं कि जो वजीर सबसे छोटी उम्र का है—बह मिस्टर चड्ढा है । वह कभी सप्लीमैंटरी के लिए यह नहीं कहेगा कि इसके लिए मुझे और टाईम चाहिए । जवाब तैयार मिलेगा । चौधरी भजन लाल जी आठ—नौ जमाते पढ़े हुए हैं । इनको सारे महकमे को मास्टरी इस तसह से है कि कभी नहीं कहेंगे कि मैं इस सवाल का जवाब फिर दूंगा । वह हर वक्त तैयार रहता है रंडी रहता है । तो मैं ऐग्रीकल्चर महकमे का बड़ा मद्दा हूं और इस ऐग्रीकल्चर महकमे से ज्यादा मद्दा उस किसान का हूं जिसने ज्यादा अनाज पैदा करक दिया सारा क्रैडिट भजन लाल जी या दौलता या यह हाउस न ले । जिस किसान ने आपको डैफिसिट पोजीशन से निकाल कर 16 लाख टन अनाज ज्यादा दिया उस जमींदार की तरफ आपको देखना पड़ेगा कि उसके अनाज का भाव उसकी मेहनत के मुताबिक मिलता है या नहीं । इसमें शरमाने की बात नहीं है । हम प्रोड्यूसर्ज हैं । जैल सिंह प्रोड्यूसर है बंसी लाल प्रोड्यूसर है त्रिपाठी जी प्रोड्यूसर थे और अब बहुगुणा जी प्रोड्यूसर बनेंगे,

नायक प्रोड्यूसर है जो भी प्रोड्यूसर चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें सैन्टर में फाईट करना चाहिए उन्हें शर्माना नहीं चाहिए और किसान के अनाज के उचित भाव लेने के लिए अपौलोजैटिक नही होना चाहिए इस रिक्वैस्ट के साथ मैं इस ग्रांट से आगे चलता हूं ।

चेयरमैन साहब मैंने ला–एड आर्डर की एक बात कही थी और वह बात हरिजनो वाली जो डिस्कशन चल रही है उससे कनैक्टिड है । मैं गवर्नमैंट को मुबारिकबाद नहीं दे सकता जहां तक काज का ताल्लुक है । जमीन का जो टुकड़ा हरिजन के कब्जे में है क्या वही आलू के बीच के फार्म के लिए इन्हें चाहिए था. और थोडी जमीन पडी थी हरियाणा में? क्या चांद राम जैसे आदमी को मौका दिया जाए? अगर चांद राम जी यहां होते तो बहुत अच्छा होता हरिजनों की बेचौनी के लिए और जो अर्ज के स्टेट आफ अफेयर्ज हैं, उन के लिए चौधरी चांद राम जी जाती तौर पर बहुत हद तक जिम्मेवार है । यह अपौर्चुनिटी हरिजनो को भड़काने की' इनको इसलिए दी. ग ई कि गलती से एक जमीन का टुकडा, जिस पर हरिजन बैठे हुए थे, वह आलू की काश्त के लिए सिलैक्ट कर लिया गया । चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए हाउस का ज्यादा टाईम न लेता हुआ इतना ही अर्ज करूंगा आज हरिजन इस जमीन पर पड़ा हुआ है, वह मन्दिर से भी सैकरेड है उस हरिजन के लिए जो लाखों वर्षो उस जमीन के लिए तडप रह है । उसको डिस–लोकेट करने की एक सलाईटैस्ट अपोर्चुनिटी तमम इन्दिरा की पलैन को फेल कर देगी । तमाम प्रोग्रैसिव पार्टीज को

कमजोर करती है । जब किसी हरिजन की जमीन की तरफ हाथ उठता है तो कम्यूनिस्ट कमजोर होते हैं, वह खुद स्पेशलिस्ट कमजोर होते हैं, और कांग्रेस (आर) कमजोर होती है । जो गवर्नमैटं ऐसी गलती करती है, वह खुद ऐ सी गलती की शिकार होती है । वह लोगों को एक अपौर्चूनटी देती है और जो उनको ऐमप्लायट करतें हैं, वे उनको री–ऐक्शन को तरफ ले जाती हैं । बड़ा अच्छ। सवाल किया था गुलाब सिंह जैन दे । मैं उनको फिर मुबारिकबाद देता हूं । चांद राम जी को, उनको इस हाऊस में जवाब देना चाहिए । Well, if Congress has not done anything for Harijans, where does he want to take them ? Does he want to take them to Charan Singh ? Does he want to take them to Jan Sangh ? क्या वह तमाम इज्जत–पसन्द ताकतों के पास इन हरिजनों को ले जाकर के छोड़ेगा ताकि फासिस्ट ताकतें जो मुल्क में जोर पकड़ रही हैं वे उनका फायदा उठाये । यह एक खतरनाक सूरत है । ग्वालियर में इन्दिरा जी मीटिग ऐडैरस करती हैं । लेकिन वहां उनकी मीटिंग डिस्टर्ब की जाती है और उन्हें मीटिंग छोड़ करके जाना पड़ता है । कास्टीच्यूशन के तहत विचार ऐक्सएंस करने का राईट मिला हुआ है । अगर फासिस्ट ताकतें प्राईम मिनिस्टर को नहीं बोलने देंगी तो डैमोक्रेसी कैसे चलेगी? अकालियों ने उनकी मीटिंग डिस्टर्ब की । मिस्टर जोशी भरतपुर में गये । उनर्का मीटिंग डिस्टर्ब की । फासिस्ट ताकतें मुल्क में जोर पकड रही हैं । इसलिए तमाम भाईयोंको खास करकें हरिजन भाईयों को प्रोग्रैसिव ताकतों का साथ देना चाहिए, चाहे वह

कांग्रेस (आर) है, कम्यूनिस्ट हों या कोई भी हो । उन्हें इन इज्जत पसन्द ताकतों से हरिजनों को दूर रखना चाहिए । मुझे डर है कि कांग्रेस की थोड़ी सी गलती 'गलत आदमियों के हाथ में ऐक्सरलायट होके, गलत ऐक्सप्लायट न हो । गुलाब सिंह जी के सवाल का जव चौधरी चांद राम जी को देना पड़ेगा कि ये हरिजनों को कहां ले जायेंगे जिनको कि ये भड़का रहे हैं? अगर काग्रेस (आर) में जाने की हिम्मत नहीं तो सी 0 पी 0 आई 0 में जाने की हिम्मत होनी चाहिये । वहां तो कैद होती है, मैंने भुगती है । मुझे वह दिन याद है जब मैं अम्बाला जेल में पड़ा था आंर गर्मी में हार्न बजते थे । फांसी वाली कोठरियों में मुझे रुक साल सात महीने रखा था 'और शिमले में जब कारें पहुंचती थीं और उनके हार्न बजते थे तो मुझे ख्याल आता था कि लहरी सिंह गया, रणजीत सिंह गया, फलाना गया और मैं था यहां पड़ा हुआ । कैद एक बड़ी मुसीबत की चीज होती है । या तो सोचे कि सी ० पी ० आई ० की तरफ हरिजनों को ले जायें well and good, कांग्रेस से आज ही ले जाओ, कोई हर्ज नहीं, वरना बाबा कांग्रेस में तो पडे रहने दो क्यों मुल्क की और इन हरिजनों की मिट्टी खराद करते हो? मैं इस बात को चौधरी चांद राम जी से कहुंगा और जो चांद राम जी के विरोधी हैं, उनसे यह अर्ज करूंगा कि इतनी इर्म्पोटैसं चौधरी चांद राम और चौधरी दल सिंह जी को न दो कि इस हाउस का करफी कीमती टाईम इन पर खर्च हो । यह इतने इर्म्पोटैंट आदमी नहीं हैं जितने आप सए बना रखे हैं और सवेरे से कह रहे हैं हाय चांद राम हाय दल सिंह, हाय चांद राम, हाय

दल सिह । यइ वात रहे है? क्या और भी कोई टौपिक है? चेयरमैन' महोदय, मैं हरिजनों के वारे मैं और एग्रीकल्चर के बारे में कह करके फिर ला एण्ड आर्डर की तरफ आता हूं । मैं बधाई भी देता हूं और क्रिटिसाईज भी करना चाहता हुं बधाई तो डस बात की देता हूं कि हरियाणा पहली स्टेट हँ जिसने लैंड–रिफार्म के वक्त मन्दिर, गुरुद्वारों और ये जो दूसरे पाक स्थान हैं, उनको कोई जमीन नहीं दी है । मैं दिले आजारी तो नहीं करना चाहता । लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये बड़ी पाक जगहें हैं तो वहां पर परमात्मा का नाम तो लो भाई दूसरी बाते मत करो । इनका हमने लैंड रिफार्म में कोई जमीन नहीं दी है जबकि हर स्टेट ने दी है । एक चीज जो अकाली भाई पंजाव में करते रहे और हिन्दुस्तान में करते रहे, वह बात बंसी लाल ने, पोसवाल ने दौलता ने और इन्होंने सब ने मिल कर करनी पड़ेगी । वह बात यह है कि इन गुरुद्वारों को सिवाये अपने गुरुओं की पूजा के दूसरे पोलिटिकल कामों के लिये इस्तेमाल नहीं होने देंगे । अकालियों ने करनाल में इसकी कोशिश की है । गवर्नमैंट को इस बारे में कलीयर वार्निग दे देनी चाहिये कि यह हरियाणा की सैकुलर स्टेट, ऐसा नही होने देगी । यह इस बारे में भी हिन्दुस्तान में लीड करेगी कि टैम्पल से, गुरुद्वारे से, अगर कोई पोलिटीकल मूवमैंट चलाई जायेगी तो उसका सिर कुचल दिया जायेगा । सिर्फ दकर 107,151 और 144 ही न लगाई जाएं बल्कि –डके की चोट पर मीटिंग को जायें, मुकाबले में और समझाया जाये कि वह भगवान का घर है, गुरु गोविन्द सिंह का धर है,

और गुरु नग्नक का घर है, यह तहरीक चलाकर असैम्बली के इलैक्शन लड़ने का घर नहीं है । मेरा इलैक्शन पैटीशन एक हिस्टरी है । ओम का झण्डा जव इस्तेमाल हुआ तो उस पर गजेन्द्र–गडकर ने भी प्रेज को । इसलिये मेरी अर्ज ला एण्ड आर्डर पर सीधी सी है कि हरियाणा की जमीन पर कोई कम्युनल पार्टी किसी रिलीजियस प्लेस को अगर इस्तेमाल करती है तो हम सब को गवर्नमैंट का साथ देना चाहिये कि उसकी सख्ती से कुचले लेकिन दफा 107, 151 और 144 का सहारा लेकर नहीं । अगर दफा 107, 151 और 144 का सहारा लेकर काम चलता तो अंग्रेज कभी हिन्दुस्तान से नही जाता । हमें पोलिटीकल तौर वे इतना मजबूत होना चाहिए कि हम लोगों को ऐजुकेट कर सके । मुझे चेयरमैन साहव, रहम आता है, तरस आता है, चौधरी श्याम चन्द जी मुझे माफ करेंगे और दूसरे हरिजन भाई भी मुझे माफ करेंगे । एक अपोजीशन का भाई तो हरिजनों को भड़का जाये और पैसे भी ले जाये लेकिन भड़काने के लिये क्या तुम्हारी जबान बन्द थी? क्या तुम उस आदमी की पोल नहीं खोल सके कि यह पाखण्ड कर रहा है, इसको चन्दा मत दो? इसको 20,000 रुपया चन्दा क्यों दे रहे हो? मेरे भाई, आपको डंमोक्रेटिक ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिये । चौधरी चांद राम को न बी0 डी0 ओ0 चन्दा ला कर देता था, न तहसीलदार लाकर देत था और न नायब–तहसीलदार लाकर देता था परन्तु चौधरी चान्द राम जी के लैक्चर इस चन्दे को लाते थे । अगर तुम्हारी जवान बन्द है तो उधार मांग लो, दौलता को ले चलो (हंसी) तो क्या मुसीबत पड़ी हुई है? पोलिटीकल लडाई

लड़ी, अगर लड़ना है, यह कोई तरीका हूँ? चौधरी चान्द राम को अपनी हैसियत क्यों एक्सपोज करते हो? क्या तुम सव कुलैक्टिवली इस काबिल नहीं थे कि लोगों को समझा सको कि जेल भी न जाओ और इसको पैसे भी न दो । यह आप अपनी हार मान रहे हैं वह पोलिटीकल डिफीट है । इसको आप ल्क्सैप्ट करो विद ऐस पोलिटीकली इस आदमी ने तुम सब को हरा दिया है । (विध्न) चेयरमैन साहब चौधरी चान्द राम जी से मुझे जितनी ना–इत्फाकी है, इनको उससे बहुत कम है क्योंकि मैंने उनकी वजह से सफर किया है । मैंने बगावत की, हम सब ने बगावत की जिसे ये बदलू दल–बदलू कहते हैं । हमको दिल्ली से पैगाम आया मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि फलां आदमी को निकालना है । चेयरमैन साहब हमने उसको निकाला । चौधरी चान्द राम और मैं दिल्ली गए । हम वहां पर हां भर कर आये कि हम इकको कांग्रेस गवर्नमैंट डिक्लेयर करेंगे और नैक्सट –डे राव साहब मान गए हमने कांग्रेस गवर्नमैंट डिक्लेयर कर दी । चौधरी चान्द राम जी चौधरी श्री चन्द जी के हाथ लग गए और जो हमारा करा कराया काम था वह सारे का सारा खराव कर दिया । वो भी अभज अजी लिहह फिरते हैं और मैं भी लिए फिरता हूं (हंसी) मगर आज ये . सारे खिलाफ हो गए । चौहान के मकान पर हमारा फैसला हुआ कि हमने अनडिजायरेबल आदमी को लीडरशिप से हटा दिया है, इसको वे डिक्लेयर कर दें । वे हमारी. गलती को कडोन करले–के लिए तैयार थे । मैं तो चौधरी चांद राम जी की पोलिटिक्स की सख्त नुक्ताचीनी करता हूं । लेकिन एक बात की मुबारिकबाद देता

हूं कि वे इतने हरिजनों के मुकाबले में 1 लाख 20 हजार रुपया चन्दा ले आया और ये बालक दे खते रह गये । हाउस में आ कर बंसी लाल जी को बताने लग गये कि हम यहां पर गाली देंगे, बाहर तो हम इस काबिल थे नहीं । (विघ्न) चौधरी चान्द राम जी इस बात के बड़े गुनाहगार हैं और वह क्लास हरिजनों की' बड़ी भारी गुनाहगार है जिसने कांग्रेस के सहारे से एक गलत श्रम उस वक्त इस सरे जमीन में, हरियाणा में फैलाया था कि हरिजनों को जमीन मिलेगी । पंडित जवाहर लाल नेहरू आए और रोहतक के वैश्य हार्ड स्कूल के सामने, मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत बड़े जलसे में उनसे कहा गया कि आप इलैक्शन मैनिफैस्टों में यह बात लिखो कि हरिजनों को जमीन मिलेगी । वह पहला इलैक्शन था जो कि मूल्क आजाद होने के तुरन्त बाद हुआ था । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जमीन. रबड़ नहीं है, जिसको बढा कर मैं दे दूंगा । किसी भी जिम्मेवार आदमी ने वे बातें नहीं कहीं । मुझे चांद राम की वह पोजीशन याद है 1952 की, मुझे वह गीत याद है जिसकी गवाही फूल सिंह कटारिया है .––

''डूघे डूघे खेत दिवाएगा चौधरी चान्द राम जी

मैंने चौधरी फूल सिंह को कहा कि भाई, तुझे वोट नहीं मिलेंगे, वोट तो डुघे डूंघे खेत दिलवाने वाले को मिलेंगे । अब डूघे डूंघे क्यार अगर वे चौधरी चांद राम को दे दें तो क्या हम गंगा जी नहाने जाएं? (हंसी) दो–दो अढाई–अढाई बीघे जमीन तो हमारे हिस्सों में आई हुई है । हमारी जमीन पर लैडंलैस लेबर

पहले ही फालतू हो चुका है । जाटों के, गूजरों के अहीरों के, खतरियो के, जो रेचारे वैस्ट पाकिस्तान से आकर काश्त करने लगे हैं, अपने ही बालक इतने फालतु हैं कि न तो हमें हरिजनों के सीरी चाहिएं और न कोई और चाहिए। हमें तो अपनों का पता नहीं कि क्या करते हैं? जमीन से तो हरिजनों का कोई सरोकार हमें नहीं, चेयरमैन साहब कोनहीं और मुझे नहीं हिस्टरी में इकौनौमिक डिवैल्पमैंट को बिलकुल खत्म कर दिया और मजबूर करदिया दि तुम जमीन की तरफ मत देखो, भले ही और कुछ देखते फिरी । जमींदारों ने तो आपकी जूती बनानी छीनी नहीं, आपके जूते बनाने की काम तो बाटा ने छीना है, वह बनाता है, उसका सिर फोड़ी, धानको की खड्डी जिसका कपड़ा मेरी ताई और दादी पहना करती थी, वह बेचारे पोसवाल ने और मित्तल ने तो खोसी नही, कही आप लोग इनके पीछे पड़ जाओ, ये बेचारे गांव के गरीब बनिए हैं, कभी इनके पीछे पड़ जाओ खाहमखाह भें वह तो उन मिल वालों ने छीनी हैं जो कि एक दिन में ही खद्दर के मुकाबले में करोड़ों–करोड़ों यार्ड बढ़िया कपड़ा बना देते है । जमींदार के पास देने के लिए कुछ नहीं । शहर वालों को भी ये बहकाते फिरते थे । कहां गई वह अर्बन सीज्गिं जिसकी रूरल सीलिंग के साथ बात करते थे? वह आज खटाई में पड़ी हुई है । आज कोई जमीन देने को नहीं है । अगर थह ऐरोगैस हूँ, तो ऐरोगैस ही पडी चेगी । मैं खास तौर पर जमीदारों की तरफ से बोल देना चाहता हूं कि जो आदमी लद्दाख में खड़ा होकर देश की हिफाजत कर सकता है वह जो दो–दो अढाई–अढाई खूड जमीन

के उसके पास रह गए हैं, उनकी भी हिफाजत करेगा । हरिजन भाईयों मुंह धो कर बैठ जाओ? कुछ नही मिलेगा । (विस्कूं) चांद राम हो चाहे सूरज राम हो, जमीन के बारे में हम ऐसी बातें सहन नहीं कर सकते । जमीन कोई आसमान में थोडे उड़ती है, जमीन तो जंगल साफ करके हमने आबाद की थी । चेयरमैन साहब, मैं एक और बात अर्ज कर देता हूं । यह बजट मुझे निराश भी करता है । यह वह बजट है जो गांव के बनिये के लिए कुछ नहीं बोलता कि उसकी हिफाजत कैसे होगी । चेयरमैन साहब, अगर किसी ने इकोनोमिक सर्वे देखा हो तो यह पता चलेगा कि गरीब हरिजन भी हूँ और गरीब जाट, गुज्जर, अहीर, रोहड़ भी होंगें, लेकिन गांव में जो बनिया बैठा है उससे ज्यादा गरीब आज के दिन हरियाणा के देहात में कोई नहीं है । शहरों मै जो आबादी गई वह जमीदारों और मजदूरों की गई । वैस्ट पंजाब से जो आबादी आई वह सारे के सारे दुकानदार आए, सुपीरियर दुकानदार आए । मेरा बनिया जो गांव का है, उसकी कोई लड़की बेटी लगती है, कोई बहू लगती है, कोई पोती लगती है क्योंकि वह गांव का पार्ट ऐंड पार्सल था । वह गरीब तिजारत के वह हथकंडे नही अपना सका जो उन लोगों ने अपनाये, जो हमारे दूसरे दुकानदार बाहर से आये थे । मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं । मेरा जो बनिया है वह मर गया । वह खेत में जा कर लिपस्टिक बेच आएगा क्या?

मेरे गांव के बनिये की तो वह बुआ लगती है, लडकी या बेटी लगती है । वह तो आए के दिन मारा गया । न तो उसके

पीस वह टैकनीक हे न उसके पास ब्यूरोक्रेसी है. चाहे वह हरियाणा की हैं, चाहे पंजाब की बै, सारी व्यूरोक्रेसी तो मेरे साथ आई थी 1947 सें । हरियाणा में क्या हमारा राज है? पंजाबियों का राज है । यह सही बात है । आज व्यू रोक्रेसी ऐंटी रहा है और विलेज ऐटमौसफियर भी ऐंटी बनिया है । एक गरीब आदमी को धनाढ्य आदमी मजाक करते हैं । एक–एक आदमी आज कलकत्ते की पटरियों पर जिस तरह से 10–15 से घूम राह है उससे तो यह साफ है कि इस इकोनौमी से जिस तरह से हरिजन आउस्ट रहा है, उसी तरह से रूरल एरिया से ट्रेडीशनल बनिया आउस्ट हो रह है । जाट बनिया जमीदार बनिया या पंजाबी बनिया जो रिच्च क्लास है. जिसके पास खेतो से पैसा आता है. का इन्कम का कोई और सोर्स भी हे. वह ट्रेडीशनल बनियों को मार्किट से आउस्ट कर है इसके बारे में गवर्नमैंट को सोचना चाहिए । है इसके बाद मैं बैकवर्ड क्लासिज के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं । को ये नाई, धोबी, तेली, लोहार हैं, ये सात फीसदी के करीब हैं । ये तो असैम्बली के मैम्बर भी नहीं बन सकते हैं । कोई भी पार्टी इनको टिकट दे कर देख ले, हार जाएंगे । हमारी इकोनौमी ही इस की है इसमें इन बेचारों का या किसी पार्टी का क्या कसूर है? हमें इसे आब्जैक्टिविटी को स्टडी करना चाहिए और उन्हे स्कूल प्रेजैंटेशन देनी ही चाहिए किसी तरीके से । मैं फिर अर्ज देता हूं कि ये लोग बनियों से खुशहाल हैं । आज जो नाई शहरों के अन्दर शिफ्ट कर रहा है गांव के वनिये से खुशहाल है । बैंकवर्ड आदमी तो ये हैं हरिजन तो रिच क्लास है । तो मेरी

यह कि बैकवर्ड तबके के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए (विघन) मैं ज्यादा टाईम न लेता हूं दो ही मिनट चाहूंगा । एक बडा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया था लाल। बनारसी दास अगर हरियाणवी लैग्वेज को कोई स्टडी करे तो यह बडी ऐक्सप्रैसिव है । यह जो हैंग–ओवर है ऊखल चढा, उन्होने उसका नाम रखा है अगर बाजारा कूटने लगे तो उसमे कुछ दानें पड जाते है और मोटा सा चिड़ा यानी गुलाब सिंह जैन जैसा, मेरे जैसा, (हंसी) चीं चीं करती है उन दानों को उठा कर ले जाता है और चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है। यह है । बड़े ऐक्सप्रेसिव वर्डज में मैं अर्ज करुंगा । मैं वार–रुम में वकीलो से पूछता रहा जो कह इंगलिश जानते हैं कि मुझे ऊखल चढे का तर्जमा बता दो जो लिटरेरी हो लेकिन इसका मेच नही है । (विध्न) उस तरफ से कोई भी ऐसी स्पीच नही होता जिस में चीफ मिनिस्टर की बडाई न हो । मैं भी बड़ाई किए बगैर नही मानता चाहे कुछ भी हो जाए । लेकिन मैं कर्ज कर देता हू कि चीफ मिनिस्टर साहव इस बारे में हारे हैं । मैं कुछ आफी सर्ज को जानता हूं सरदार प्रताप सिह कैरों के वक्त में भी थे । आज वे इन के मुंह लगे हुए हँ । प्रताप सिंह कैरो के राम किशन आया । उस वक्त भी वे उन के मुंह लगे थे । फिर जब भगवत दयाल जी आए । है उस वक्त भी वे वहुत नजदीक थे । जब भगवत दयाल जी के बाद राव वीरेन्द्र सिंह तो रोज शाम को उनके पास उन्हे' बैठा देखा करता था । जो लोग इनडिस्पैंसेबल है वो तो डिस्पैवल रहेंगे । वो तो भाई चाहे ऊखल में कोई भी मूसल मारें, छोड़ेंगे नहीं, दाना वहां से जाएगें मुझे

अच्छी तरह याद है, एक बार भगवत दयाल जी ने अपनी तकरीर में बेरी में जैसा कि चौधरी साहब, आपकी तकरीर में उस तरह का कलफ नही आया जिस तरह खंडवा हो जाता है । तो चौधरी साहब स्पीच मे कलफ ला दिया करते थे । जब राव बीरेन्द्र सिंह की वक्त आई तो दही चौधरी साहब उनकी स्पीच में कलफ लगा दिया करते थे । अब चुन वाली बहुत आई तो जलसा चाहे कलानौर में हो, चाहे बैरी में हो, लेकिन स्पीच में तो कलफ यही साहब लाते हैं । यह क्लास मर नहीं सकती । इसमें अपने गुण होते हैं । अपने गुणों की वजह से वे सरवाईव करते हैं क्योंकि वे उनके नजदीक रहते हैं । अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मैं अर्ज करूंगा कि अच्छी बात है अगर वे ऊखल चढे लीडर न होने दे, लेकिन इस चीज को घनी दूर रहा जाए। वे तो इस चीज को इतनी दूर ले गए कि कोई छोडा ही नही । यह ठीक है कि मैं दरख्त यदि आज लगाओ तो बीस साल में लग जाएगा, फसल छः महीने मे की जाएगी, लेकिन किसी सूबे की, किसी नेशन की लीडरशिप या नैशनल लीडर रोज पैदा नहीं होते, मुद्दतों लगते हैं किसी लीडर को बनने में । अगर कोई लीडर का समझ कर कि यह मेरा राईवल बनेगा, उसको जलील करेगा उसको खत्म ही कर देगा तो यह नैशनल वेस्टेज होगी ।

16.00 बजे।

मैं घमण्ड से कहता हूं कि बंसी लाल जी की कई खूबियां मुझे बहुत प्यारी हैं । यह कोई खुशामद की बात नही है

। हमारा इसका रिश्ता बडा डिफाईन्ड । दोस्त तो अभी को तैयार नहीं, दुश्मन मैं बनने को तैयार नही, यह अपना स्टेटस है (हंसी) स्टेटस यही रहेगा हमसे इसमें गुलाब सिंह जी, ज्यादा न डरा करो, मैं ज्यादा करीब नहीं जा सकता उसके, यह अपनी ही मौनोपली रहेगी । (हंसी) मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है है चीफ मिनिस्टर साहब को मैं याद दिलाता हूं हिस्टरी का एक वक्त । दिल्ली में एक हुक्मरान हकूमत कर सकता था । वह हुक्मरान एक पैसा शाही खजाने से नहीं लेता था जिस तरह बंसी लाल जी नहीं लेते है यह कुरप्शन–कुरप्शन की बात में मैं यकीन नहीं करता । यकीन होगा तो उस दिन कह दूंगा जो इन्होंने मैमोरैडम दिये हैं, वे कोई डायरैक्ट बंसी लाल के खिलाफ मैमोरैण्डम नहीं हैं । डिपार्टमैंट्स की इर–रैगुलैरिटीज के खिलाफ मैमोरैन्डम है । न वह कुरप्ट है, न वह हो सकता है न उसकी टैम्मरामैंट कुरप्शन की एँ दो मिनट उलटी आ जाये तो वह बर्दाशत नही कर सकता है चेयरमैन साहब कुरप्शन करने के लिए तो बड़ा ढूगा पेट चाहिए ताकि बोलने भी न दे किसी आदमी को और अपने आप खाये जाए दाबे जाएं (हंसी) चेयरमैन साहब मैं उनसे एक अर्ज करना कि कुरान शरीफ से कापियां लिखलिख कर निर्वाह करते थे वह बादशाह । उनकी बीवी टोपी सीती थीं जिस तरह से बंसी लाल जी की चौधराइन सुबह उठकर शाम तक पांच नहीं तो रुपये का काम करके सोती है । वह कभी चीफ मिनिस्टरी के वहम में नहीं बैठती है । कही वह बिनौलों में लाग रही है कभी वह कहीं और लाग रही है । बालिक भी इसी तरह हैं एक

बालक आडे सी लत्ता धोता पावेगा एक आगे सी पावेगा । चेयरमैन साहब आप यह समझें कि क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार है इसलिये मैं बहुत तारीफ कर रहा हूं रिश्तेदारी तो अगला जानता ही नहीं किसी की । (विघ्न) हकीकत यह है कि जितना सिम्पल लिविंग हमारे सी0 एम0 का है उतना किसी का नहीं है । बेचारा छः आने सात आने की रोटी खाए और अपने कमाने मैं अपनी जाखट–चूखट आपे धर–धूर ले, बालकों के भी भरोसे नहीं और किसी नौकर के भी भरोसे नहीं । लेकिन उसमें एक ऐब भी बहुत भूण्डा है । औरंगजेब की भी यही आदत थी । की कुरान शरीफ लिखकर रोटी खाता था, बेगम टोपी बनाती थी पर जो दिल्ली के तख्त की तरफ देखता था, उस साले की आंखे निकलवा के डाल देता था (हंसी) हाथ तुड़वा देता और उसे मरवा देता था । उसने अपने वक्त में दिल्ली कानी लखावन वाला आदमी नही छोड यही हाल इनका है । अगर बंसी लाल जी को बहम हो जाये कि देवी लाल लखा चुका है, यह फलाना लखा चुका है तो यह सह नहीं सकता । सारे साफ कर दिए । पता नहीं क्यों लिए बैठा है? हमारी कित ताकत है इस ओड देखन को? ये हमने जी लेण दे, वही इतनी सी बात है, (हंसी) और हम उसतें के मागें? (हंसी) चौयरमैन साहब, और क्या, कुछ तो कट गया.... (हंसी) यह बात मैंने उसते पहले दिन ही कही थी ।

चेयरमैन साहब वह जो डायनेमिजम उसमें हैं वह किसी और लीडर में नही है । किसी ने खैरात नहीदी है जिसमें वह डूबे

मरता । किते भगवत दयाल भड़काया किते नन्दा फजी करया. किते केरा क्यूकर पहुचाया आगे ताई । इस ताकत को जो ताकत इन्होंने हासिल की है, कोई छीन नहीं सकता । .....और स्टेट में डिसीडैन्टस हैं । इस सी . एम. का कोई डिसीडैंट नहीं । बहन चन्द्रावती तो यूं ही भाई–बहन के प्यार से लड़ पड़ी थी, कोई डिसीडैन्ट है वह? इधर सिवाये जनसघ वालों के कोई भी अपोजीशन नहीं । विरोधी दल, विरोधी दल, कहा जाता है, क्या कहे हम? हम तो सारे ही बंसीलाल हैं, कौन सा न कहता है, वह आके मैंने बताओ । (हंसी) किसी ने नोकरी थ्यागी, किसे ने ना थ्याई । जिसको थ्यागी वह बड़ा राजी है । दीखता कोई ना रिजक राम भी । हखारी लाल जी साल भर तक यह कहता रहा है कि चौधरी बंसी जी मुझे बोले, मैं उनको यु बोला । जो कुछ चौधरी बंसी लाल जी मुझको कह गये, वे दोनों बातें चौधरी हरद्वारी लाल की कही हुई थी । मुझे याद है कब कही थी उसने । चेयरमैन साहब, वहां पर कोई दल–वल नहीं है । यहां पर तो एक बंसी दल ही है । दो जनसंघ वाले हैं बेचारे है पता नहीं अगली बार पावेगे कि ना पावेंगे (हंसी) बड़ी ज्यादती है चेयरमैन साहब कि चूरमा भजन लाल और कांग्रेस–कांग्रेस के मैम्बर खावें । हमने क्या बिगाड़ रखा है? चेयरमैन बंहब, डिप्टी स्पीकर ..... लंच दे उसमें भी हमें कोई नहीं शामिल करता । यह तो ज्यादती है साहब यह डिस्किमीनैशन बड़ी जबरदस्त है यह दूर होनी चाहिए यह हाउस ऐसा है चेयरमैन साहब मैंने एक बात पहले दिन कही थी अपने पुराने स्पीकरको बाद होगा उनके कमरे में कही थी यह

वह हाउस है जो आइडियल हाउस हो सकता है, यह वह हाउस है जहा किसी मैम्बर को दूसरे मैंम्बर पर हमला करने की जरूरत नहीं ढै ' यह हाउस है जिसके सी 0 एम 0 को वह ताकत हासिल है जो कि हिन्दुस्तान के किसी सी ० एम ० को हासिल नहीं । ....पांच सात साल के सी ० रुम ० हैं. वो कोई एक दिन के तो नहीं हैं । तो मेरी अर्ज यह है यह गवर्नमैंट बड़ी फिट गवर्नमैंट हूँ और यह बजट बहुत फिट बजट है । माडा सा सी ० एम ० साहब का जो मुंह का ऐंगल है 125 का वह 90 ताई आ जाये तो सब कुछ ठीक है । चेयरमैन साहब, शुक्रिया ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय चेयरमैन साहब, कई दिन से बजट पर इस हाउस में चर्चा चल ची है और अब डिमान्डज पर चर्चा चल रही है । अभी दोलता साहब हाउस में वोल कर गधे हैं । मैं आपके द्वारा इन ट्रेजरी बैंच्चिज के भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि यदि वे उनकी मनो–कामना पूरी कर दे' तो वहुत अच्छा रहेगा नहीं वे बेचारे बहुत बेचौन रहेंगे । मेरी अर्ज यह है कि उनको एक तरफ कर दें । आप उनको बीच में लटकाते हैं और जब वे खड़े होते हैं तोवे इसी सशोपंज में रहते हैं । उन्हें स्वयं पता नहीं लगता कि वे क्या बोलते हैं क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोल गये हैं । इसलिये मैं यह कहुगा कि उनकेमन में स्थिरता लाना आपके हाथ में है । आप उनको कांग्रेस मेंशामिल कर लीजिये एक वही अकेले आदमी क्या आपके दल को तोड़ देंगे? वह तो ये कहते हैं कि मैं जबरदस्ती इसमें हूं

आप मानें चाहे मे मानें । मेरी गुजारिश यह है कि आप इस चीज को खत्म कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा ।

बजट के बारे में जो चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल के बजट में 14 करोड 70 लाख रुपये का घाटा था । उसके बाद भूमि–कर लगाया गया दूसरे कर लगाये गये और शराव की बिक्री बढ़ायी गयी । यह सारा कुछ करने के बाद 5 करोड़ 19 लाख रुपये का घाटा पिछले साल के बजट में रह गया जबकि पिछले साल डिवैल्प मैट के लगभग सभी काम एक तरह से रुक गये थे । जो इस साल का बजट आ रहा है उसमे भी 17 करोड़ 97 लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है । मैं यह समझता हूं कि जब पिछले साल का घाटा अब तक कवर नहीं किया जा सका है तौ यहं 18 करोड़ रपये का घाटा कैसे पूरा होगा? अभी इस बजट में नये करो को तो बात नही कही गई है लेकिन इतने बड़े घाटे से यह साफ दिखायी देता है कि कर तो लगाने ही पड़ेंगे । कर तो यह सरकार लगायेगी ही यह अलग बात है कि यह कुछ दिन के बाद लगायेगा या किसी और ढ़ंग से लगायेगीं । उन करो के लगाने से मंहगाई कितनी बढेगी इसको ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है । इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस घाटे को कम करते के लिये जो जनरल–ऐडमिनिस्टेरशन यानी साहब प्रशासन है उसमे सुधार लाया जाये । उसकी वजह से भी यह घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है मैं चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये क्येकि

हमारे ऊपर जहां बजट का घाटा बढता जा रहा है बहा उसके साथ–हीं–साथ कर्जा भी बढ़ता जा रहा है । कई भाई तो यह भी कहते कि कर्जा बढ़ना तरक्की की निखानी है । हो सकता है कि किसी भाई के लिये यह ठीक हो लेकिन सवाल यह उठता है कि वह कर्जा दिया कैसे जायेगा? वह कर्जा वढुते–थढुते बहुत हो गया है । हमें यह देखना चाहिये कि हमारे पास साधन कितने हैं और उन साधनों से हम कितना कजी वापिस कर पायें हैं क्योकि 18 करोड़ के लगभग का जितना हमारा घाटा है उतना तो हमें पिछले कर्जा का केवल सूद–चद का ही देना है और जो कर्जा आगे बढेगा उसका फिर पता लगेगा । मै यह कह रहा था कि इस घाटे को कम करने के लिये डिमान्ड नं० 2 जो सामान्य प्रशासन के लिये है उसमें सुधार लाया जाये ताकि इस फजूलखर्ची को बचाकर जो यहां चल रही है हम कुछ बचत कर सके और जो डिवैल्पमैंट के काम रुके हुए हैं, उनको कुछ आगे चेयरमैन साहब. अब मैं डिमान्ड नं. 14 जो फूड ऐन्ड सप्लाईज के बारे में हं, कुछ कहना चाहूंगा । पिछले साल गेहूं का व्यापार इस सरकार ने अपने हाथ में लिया । चाहे सरकार आँकडे कुछ भी दे, कहने के लिए कूछ भी कहे परन्तु यह साफ है कि उस व्यापार में सरकार बिल्कुल असफल रही है फेल हुई है । सरकार गेहूं के व्यापार में अपने निशाने को भी पूरा नहीं कर पाई बल्कि हालत यह रही कि वह निशाना भी पूरा नहीं कर सकी । रुसके साथ–साथ जो महंगाई रोकने की बात सरकार करती है, उसने लोगों से 76 रुपए के भाव से गेहूं खरीद कर मुनाफा क्यके पब्लिक को वेचा । अगर सरकार

इस साल मुनाफा नहीं करती, सरकार अपने हाथ में नहीं लेती तो खुले बाजार में 76 रुपए के बजाय 90 और 95 रुपये फी क्यिंटल गेहूं बिकता । (इस समय कोरम को घंटी बजाई गई ।) इस प्रकार से गेहूं के व्यापार से जो जनता को लाभ होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ क्योंकि उस समय किसान को 76 रुपए के भाव पर देना पड़ा ।

किसान से जबरदस्ती लिया गया या मजबूरी में किसान को देना पड़ा । सरकार ने जब गेहूं 76 रुपए खरीदा और 104 रुपए के भाव से डिपुओं पर उसको बेचा तो इससे गरीव आदमी को कोई सहुलियत नहीं मिली बल्कि उसके ऊपर बोझा पड़ा । यह बात समझ में नहीं आती कि जब सरकार ने 78 रुपए के भाव गेहूं खरीदा तो 104 रुपए के हिसाब से क्यों बेचा? इससे साफ जाहिर है कि सरकार पैसा कमाना चाहती है । उस वक्त किसान को लूट लिया और अब खाने वाले को कोई लाभ नहीं है । किसान को पैसा भी कम मिला और व्यापारी से काम भी छिन गया । काफी व्यापारी जो इस काम में लगे हुए थे. उनसे काम भी चला गया । जो काम व्यापारी लोग मुद्दतों से करते थे, वे आज सोचते हैं कि कौन सा काम किया जाए । हरियाणा के अन्दर–कच्चे आढतियो ने गेहूं के व्यापार का काम किया लेकिन ऐसा लगता है कि अगले साल यह पद्धति भी बदल जाएगी और फि र व्यापारी वर्ग बेकार हो जाएगा । गेहूं का व्यापार सरकार के हाथ में आने से आम जनता को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा बल्कि मैं समझता हूं कि

जो सरकार ने अपने डिपुओं पर गेहूं के भाव बढ़ाए उसकी वजह से दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ते चलेगा और अभाव भी बढ़ा । आज हालत यह है कि कोई चीज नहीं मिलती । इसलिए सरकार को इस ढंग से चलना चाहिए कि किसान को पूरा, भाव मिले और दूसरे लोगो को काम मिले । अगर किसान को पूरा भाव नहीं मिसएगा तो देश में पैदावार बढेगी नहीं बल्कि घटेगी । गेहूं के भाव तय करने में अगर लागत और पैदावार का हिसाव लगाएं तो गेहूं का भाव पिछले साल 110 रुपए फी क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए था । गले का भाव जो साढ़े बाच्छ रुपए चल रहा है, वह पन्द्रह रुपए से कम नहीं होना चाहिए । जीरी का भाव सरकार ने सत्तर रुपए फिक्स किया है लेकिन खुले बाजार में वह 80 रुपए बिक रही है इसलिए उसका भाव अस्सी रुपए फिक्स करना चाहिए और आगे के लिये. क्योंकि इस वर्ष दर चीज फिजन को मंहगी मिल रही है, इसलिए किसान को नुकसान होगा, इस चीज से देखते हुए अगर किसान का गेहूं 110 रुपए से ऊपर बिके, तभी किसान का घर पुरा होगा । कृषि मंत्री ने बताया है कि हमने केन्द्रीय सरकार को सौ रुपए प्रति क्विटल गेहूं के भाव तय करने की सिफारिश की है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार को बताएं कि पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा बोझ किसान के ऊपर बढ़ा है । इसलिए उसको 110 रुपए से ऊपर अगर भाव नहीं मिला तो उसका घर पूरा नहीं होगा क्योकि' जो भी चीज आज उसको खरीदनी पड़ती है उसके भाव अन्धा धुंध बढ़े हैं बल्कि उनको भाग,। नहीं कहा जा सकता एक लूट हो रही

है । इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसान को पूरा भाव दिलाया जाए क्योंकि किसान इस देश की रीढ की हड्डी है । अगर किसान मजबूत होगा तो इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । अगर किसान कमजोर हजो र्श । इस देश को आर्थिक स्यिति कमजोर होगी और दूसरे वर्गो को भी कोई लाभ नहीं होगा । जब किसान कमजोर होगा तो मजदूर को कौन लगाएगा? दूसरे कामों में जो पैसा लगता है वह कहां से आएगा? इसलिए जरूरी है कि किसान को पूरा भाव दिया जाए ताकि वह पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर इस देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करे ।

चेयरमैन साहव यहां बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है क्योंकि बिजली हर प्रकार की उन्नति के लिए एक आधार है कृषि के लिए एक आधार है । मैं इस बारे में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा । केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के ऊपर कहा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही साथ बिजली में कटौती और बिजली की सप्लाई में अनियमितता बढ़ती जा रही है । यह दोनों बातें इकट्ठी हो रही हैं । बिजली बोर्ड का कर्जा कम होने में नहीं जता और उधर हूर साल बिजली को कटौती पता नहीं किस वक्त. कितनीं हो और किस वक्त कितनी हो इस वक्त कहा जाता है कि किसान के टयूबवैल को बारह घंटे विजली देने का फैसला हुआ है मैं सिंचाई मंत्री से कहुंगा कि वे पिछले सप्ताह की इन्क्वायरी करवाएं । पिछले सप्ताह में किसी

दिन दो घंटे किसी दिन ढाई घंटे और किसी दिन तीन घंटे से ज्यादा बिजली नही मिली । कभी रात को सात बजे आई साढ़े–आठ बजे चली गई किसी दिन ग्यारह बजे आई और सवा बारह बजे चली गई और किसी दिन साढे ग्यारह बजे आई तो डेढ़ बजे चली गई। कहा जाता है कि दो ग्रुप बनाए हैं, एक दस बजे सुबह से रात के दस बजे तक और दूसरी छः बज शाम से सुबह आठ बजे तक, इस प्रकार बिजली सप्लाई होगी । मैं कहता हूं किं यह सिस्टम भी एक सप्ताह या दो सप्ताह के करीब चला होगा और उसके बाद फिर यह चालू हो गण कि किसी वक्त शाम को बिजली नहीं आती किसी वक्त– सुबह दस बजे से रात के दम बदे तक बिजली नही आती और इस वजह से ट्यूबवैल नही चलते और घरों में भी रोकनी नहीं आती । मैं कहना चाहता हुं कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि कम से कम बारह घंटे विचार) की जो सप्लाई है, वह तो चलनी चाहिए और जिस समय से जिस समय तक बताया गया कि बिजली आएगी, उस कुछ तो विजली आनी चाहिए । अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। मैं इस बारे में कुछ सुझाए देना चाहता हूं । भाखडा से जो हरियाण। का बिजली का हिस्सा निकलता है, वह हरियाणा पूरा नहीं ले पाया है । जब तक हरियाणा बपने हिस्से की पूरी बिजली नहीं लेगा तब तक हमारे यहां बिजली का वही हाल रहेगा और बिजली की स्थिति में कोई सुधार आने वाला नहीं है । इसके लिए कब तक हमें इन्तजार करना पड़ेगा । जब तक हम उन मजबूरियों को दूर नहीं करते जिससे कि भाखड़ा से हमें पूरा हिस्सा मिले, तब तक कतई

सुधार आने वाला नहीं है । इसलिए भाखड़ा से बिजली का पूरा हिस्सा लेने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयत्न होना चाहिए । इसके साथ ही एक दूसरा सुझाव देना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर एक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि उसके बिना बिजली को जो कभी है खीर आगे तो मांग और भी बढ़ने वाली है, वह पूरी नहीं हो सकती । हरियाणा सरकार परमाणु बिजली संयत्र के लिए केन्द्रीय सरकार से बात करे और शीघ्रातिशीघ्र हरियाणा के अन्दर परमाणु बिजली सदेव स्थापित करने के लिए प्रयत्न करे । इसके साथ–साथ मे तीसरा सुझाव जो ताप बिजली घर परियोजना है, जोकि बहुत दिनों से अधुरी पड़ी है, उसके बारे में देना चाहता हूं कि उसको जल्दी –से–जल्दी पूरा किया जाए । यह 7 या 7 साल से कुछ ज्यादा की बनी हुई है लेकिन वह 7 साल से अब तक पूरी होने में नहीं आ रही है । इसके क्या कारण हैं? इसलिये सरकार को इस तरफ पूरी लग्न से विचार करना चाहिये और यदि शुभ इसको पूरा कर पाएंगे तब हम अपनी जरूरत के मुताबिक खेती को भी बढाएंगे और इसके साथ–साथ उद्योग को भी बढावा मिलेगा ।

चेयरमैन साहव, आगे चल कर मैं गरीबी के मुताल्लिक कुछ कहूंगा । हम गरीबी को काम करने के लिये यह सारे काम कर रहे हैं । गरीबी बातों से कोड़ा दूर होगी गरीबी तो तब पूरी होगी जब हम अपनी पैदावार को बढाएगे इसके लिये हमें अपनी पैदावार को बढाने की जरुरत है और इसके लिये कृषि–क्षेत्र और

उद्योग–क्षेत्र, इन दोनों का बढ़ाया जाना जरूरी है । इन दोनों तरफ जब तक हम पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक हम गरीबी को नहीं हटा सकेंगे । गरीबी तो जैसी दूसरे प्रदेशों के अन्दर है, ऐसी तो हरियाणा में कभी थी नहीं, ऐसी तो अब भी नहीं है क्योंकि यहां की जमीन उपजाऊ है और यहां के काम करने वाले आदमी मेहनती हैं इसलिये कोई आदमी यहां पर कभी भूखा नहीं मरता । जब यहां पर बिजली नहीं थी लोग तो तब भी यहां पर भूखे–नंगे नहीं थे बल्कि हरियाणा क नाम लिया जाता था कि देशों में हरियाणा जहां दूध दही का खाना । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे । हम दूसरे प्रान्तों की बात लेक र के अपने मन को शान्ति देने की कोशिश न करें ताकि पैदावार के लिहाज से हर मेहनतकश आदमी को जो पैदावार बढ़ाता है, उसको उसके मुताबिक फल मिले । तब तो कोई फायदा हो सकता है अन्यथा कोई फायदा नहीं है ।

चेयरमैन साहब. इसके साथ–साथ मैं यह कहूंगा कि पिछडे क्षेत्रो का विकास भी बहुत जरुरी है । जिन क्षेत्रो में जिस–जिस चीज की कमी रही है वहां उनको वह चीजें मिलनी चाहिये और साथ ही यह भी कहूंगा कि हरियाणा के अन्दर जो ट्यूबवैल लग रहे हैं, वह पहले 989 लग चूके हैं और आ। ले साल के लिये 450 और लगाने की योजना है । इस तरह अंधा–धुन्ध ट्यूबवैल लगाने से मेरे खाल में तो करनाल और कुरू क्षेत्र जैसे इलाकों को तो कोई रुपया नहीं होगा और थोड़ा बहुत दूसरे

डिस्टूक्स में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता । (इस समय भी अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, ऐसा हो रह है कि नीचे कौ पानी ये ट्यूबवैल खींच रहे हैं और ऊपर का पानी जमींदार के टयूबवैल्ज खींच रहे हैं और इस तरह से करने से किसी न किसी दिन ऐसी हालत हो सकती है कि यहां पर पानी ही नहीं रहेगा । वैसे इसकी शिकायत आनी शरू हो गई है । इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । इसके साथ–साथ जव टयूबवैत्ज से पानी की खिंचाई जारी रहेगी और नहरों को पक्वा करने से पानी का रिसना बन्द हो जाएगा तब इस प्रकार भूमि का पानी खत्म हो जाएगा । तो इससे करनाल और कुरुक्षेत्र जिलो की ऐसी हालत हो जाएगी जैसी कि उन जिलों की है जहां यह पानी खुश्की मिटाने के लिये ले जाना चाहते हैं । स्पीकर साहब, जहां तक नहर के पानी सिंचाई की हालत का सवाल है. आंकड़े तो ये चाहे कितने ही दियें जाएं, लेकिन हालत वैसी नहीं है । मैं खुद जमींदार हूं । मुझे पता है कि नहर के पानी से सिंचाई कम हो रही है । और इसके साथ किसान को अपने खेतों को ट्यूबवैल्ज द्वारा भी पानी देना पड़ता है जिस से उसका दुगुना खर्चा हो जाता है । तो मैं सरकारर से कहूंगा कि इस तरह अन्धा–धुन्ध टयूबवैल लगाने का कोई फायदा नहीं है । पांच–सात साल तक यह हालत होगी कि ड़स इलाके में एक तरह से जमीन सूख जाएगी और आज जो हालत हिसार और दूसरे जिलो की है, करार इस तरफ कोई ध्यान न दिया गया तो यह हालत बेकाबू हो जाएगी । इस बात का तो आज ही इलाज हो सकता है ।

योजनाबद्ध तरीके से अगर सरकार चलेगी, तभी सारी बातें ठीक ढंग से चलती रहेंगी । मैंने यह डिमांड नम्बर 15 के बारे में कहा है । अब स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 18 पर आता हूं । स्पीकर साहब, इसमें बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं । मैं उनको दोबारा सदन का समय बचाने के लिये दोहराना नहीं चाहता । ऐनीमल हस्बैडरी के बारे मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं । किस तरह से नस्ल को सुधारा जाए और किस तरीके से दूध बढ़ाया जाए, यह बातें तो पहले ही सरकार के नोटिस में हैं । इस बारे में मेरा ए क सुझाव है कि यहां से जो कमजोर, बीमार और नही पशु के नाम पर बहुत से पशु बाहर जाते रहे हैं उनको बाहर जाने से तुरन्त ही रोका जाए । कई अच्छे पशु बिक कर बाहर जाते हैं, इसके लिये मुझे दु:ख नहीं है लेकिन कमजोर पशु के नाम पर जो अच्छे पशु बाहर जाते हैं, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और यह काम बन्द करवाना चाहिए अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर यहौ के पशुओ की नसल कैसे सुधरेगी । मादा पशु एक सांचा है, जिस में बीज डाल कर नई नसल पैदा की जा सकती है । सरकार को देसी जो गायें हैं, उनको बाहर जाने से रोकने या प्रबन्ध करना चाहिए क्योंकि यदि सांचे ही न रहे तो अच्छा बीज कहां डाला जायेगा? इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार ऐसे पशुओं, को अपने पास इक्टठा करे और कहीं न कहीं इनके लिये गऊशालाओं का प्रबन्ध करके उनमें बीमार पशुओं का इलाज करवाया जाए । उन देसी गायों में जरसी और दूसरी उन्नत नसल के सांडों का बीज डालकर गयाबन करवाया जाए.

ताकि अच्छी नसल पैदा हो । तो इस तरीके से हरियाणा के अम्बर पशुओं की एक बहुत ही अच्छी नसल बडी संख्या में शीध्र पैदाहो सकती है । अगर ऐसे पशु बाहर चले गये तो हम बीज किस में डलवाकर कैसे नसल को सुधारेंगे? इसलिये इस ओर सरकार को विशेष–ध्यान देना चाहिये कि वह इन पशुओं को बाहर जाने से रोके ।

इससे आगे स्पीकर साहब, मैं डिमांड नम्बर 16 पर आता हूं जोकि इन्डस्ट्रीज के बारे में है । सरकार इंडस्ट्रीज की बात करती है । इन्डस्ट्रीज लगती भी हैं लेकिन इस से बड़े– 2 इडस्ट्रीयलिस्टस को ही फायदा हो सकता है । फरीदाबाद और हिसार में ही इंडस्ट्रीज वगैरह लगी है । लेकिन इन से कोई काम चलने वाला नहीं है, यही बात मैंने पहले भी कही थी क्योकि गांव में जो छोटे–छोटे कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, वह बड़े–बड़े कारखानों की वजह से चल नहीं रहे हैं, खत्म हो गये हैं । आपको तेली का कोल्हू गांव में नहीं मिलेगा (रूई जूनने वाला) भी कहीं गांव में नहीं मिलेगा । गने के बारे में भी मिल अगर केश नहीं कर सकता तो आप कोल्हू लगाने की इजाजत देते हैं । तो इससे क्या होता है वह उद्योग भी खत्म हो चाहै । इसी तरह से छोटे–छोटे उद्योग, कताई वगैरह के, वे सारे बन्द होते जा रहे हैं । अतरू सरकार को ग्रामीण उद्योगों को तरफ ध्यान देना चाहिये और इसके साथ–साथ दूसरे जो नई किस्म के काम हैं, जो एक–एक घर में चल सकते हैं, एक एक आदमी, दो–दो आदमी

जिनको चला सकते हैं, वैसे छोटे–छोटे लघु उद्योगों का जाल हर तरफ सरकार को फैला देना चाहिये । इससे हरियाणा को जनता की जो आवश्यकता का माल होगा, वह माल वही पर बनेगा और लोगों को मिलेगा । इस के साथ–साथ लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। सरकार की लेबर की समस्याए है। रोज हडताल होती है।

अभी श्री गुलाब सिंह जी बता रहे थे कि इतने घंटे हडताल हूई और इतने काम का नुकसान हुआ । तो वह नुकसान भी बचेगा और हड़तालें भी नहीं होंगी । जिसके घर में करने के लिये काम होगा, वह हड़ताल क्यों करेगा? तो इस तरह से जो चीजें वहां पैदा होंगी, वे वहां के लोगों को सस्ते दामों पर मिलेंगी । वहां जिस स्पिति के .लोग रहते होंगे, उनकी स्थिति के अनुसार उनको वह चीज मिलेगी और लोगों के ऊपर ज्यादा बोझा नहीं पडेगा क्योंकि जो चीज दूर से आती है उसके ऊपर आने–जाने का खर्च पड़ता है और अगर वह चीज हम वही बना लेते हैं तो वही खर्च कम हो सकता है । इसींलये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे इस ओर ध्यान देना चाहिये और कुटीर–उद्योग लगाने की तरफ ध्यान देना चाहिये । इसके साथ ही नये प्रकार के उद्योग चलाए जाएं । यदि कोई किसी बड़ी चीज का कारखाना खुलता है तो सारे ही पूजे वहां नहीं बनने चाहियें वल्कि गांव गांव में छोटे उद्योग लगाए जाएं जोकि उन पुर्जों को बनाएं । जैसे हमारे यहां शिक्षित बेरोजगार हैं, वे कस्सी लेकर या हल चलाकर

काम नहीं करना चाहते लेकिन वे मशीन लगा कर छोटा मोटा काम क्रूर कर लेंगे । स्पीकर साहव, मैं इस चीज से संबंधित नीलोखेडी को बात कहना चाहता हूं कि नीलो– खेडी एक औद्योगिक बस्ती के नरम से बसी थी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी बिना पर कहा था कि इसके अन्दर उद्योग चलेंगे । लेकिन स्पीकर साहब, आज वहां की हालत देखे । वहां कोई उद्योग नहीं है और सरकार का ध्यान उधर से हट गया है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नीलोखेडी के अन्दर, जिसकी बुनियाद इसी काम के लिये थी, वहां उद्योग चालू किए जाए । यदि बड़े उद्योग न चलाए जा सके, तो छोटे उद्योग चलाए जाएं । अगर आप वहां इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो वहां पर जो लोग निराश। की जिन्दगी से रह रहे हैं. वे भी समझेंगे कि इस शहर. की तरफ भी सरकार का ध्यान आया है । वह कस्बा जी० टी० रोड के ऊपर है और मेन रेलवे लाइन पर है । वहां हर प्रकार की आने–जाने की सुविधा है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस की. ओर विशेष ध्यान दिया जाए ।

डिमांड नहबर 23 जो सड़क. परिवहन की है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा । कुछ आंकड़े हमारे सामने आए कि 1967–68 में 406.49 लाख यात्री सरकार बसों पर यात्रा कर पाए थे और 1971– 72 में 779. 87 लाख यात्री सरकारी बसो में यात्रा कर पाए । तो सरकार ने यह कहा कि चुंकि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई ई, इसलिये यात्रियों की संख्या बढ़ी है

। लेकिन ये भूल गए कि उस समय 1 967–68 मेआधी बसें प्राइवेट लोगोंकी थीं । तो आधेयात्री उन बसों में चलते थे और आधे सरकार बसों में चलते थे । इस तरह उस समय 406 लाख थे अगर अब उस हिसाब से लगाए तो यात्रियों की संख्या आठ सौ लाख से ऊपर होनी चाहिये । लेकिन यह सखा आठ लाख, से कम हुई हैं यानी उतने भी नहीं हुए जितने कि उस हिसाब से होने चाहिये थे । इसलिये इसमें कोई बढ़ौतरी दिखाई नहीं देती है । यदि आप इस तरह से हिसाब लग।ए तो आपको पता लगेगा कि यात्रियों की तादाद कम हुई है जबकि आबादी के हिसाब से यह संख्या बढ़नी चाहिये थी । इसके साथ–साथ आम आदमी को सहूलियत मिलनी चाहिए थी क्योंकि सारी बसें सरकारी कर दी गई है । आज की डिमाड के मूताबिक सरकारी बसे पूरा नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक बसें पूरी न हों तव तक के लिये दूसरे लोगों का काम देदिया जाए जिससे कि उनको भी सहूलियत मिलेगी और यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी । एक बात इस बारे में मैं और कह देना चाहता हूं कि सरकार को अपने ड्राइवर और कंडक्टरों को यह हिदायत कर देनी चाहिये कि वे बस स्टाप से आगे या पीछे बस की रोकें । क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि बसें स्टाप से आगे पीछे खड़ी की जाती हैं और सवारियां बस के पीछे भागती हैं । जब वे बस के नजदीक पहुंचते हैं तो बस चल देती है । इसप्रकार से बूढ़ी सवारियोंको बड़ा कष्ट होताहै । इसलिये मेरी गुजारिश है कि बस स्टाप पर ही रोकी जाए । अगर सवारी न भी लेनी हो तब भी वहां पर ही रोकी जाए ताकि

सवारियों को भागने की जरूरत न पड़े और साथ ही बसे बड़ाने के लिये जो भी सुधार जल्द से जल्द लाए जा सकें, वे जल्दी लाएं ।

डिमांड नम्बर 8 भवन तथा सड़कों के बारे में है । इसके बारे में मैं वित्त मन्त्री महोदय के शब्द ही आपको सुनाना चाहूंगा उन्होन स्वयं कहा है कि अगले कुछ वर्षों में इस गतिको शायद बनाए रखना संभव नहीं होगा । तो यह एक निराशा की बात दिखाई देती है । सड़कें तो डिवैल्पमैंट का एक आवश्यक भाग है । सड़कों के बिना कोई इलाका कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, इनके बिना बड़ी मुश्किल रहती है इसलिये सड़कों की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । जैसे कई भाइयों ने नाम लेकर सुझाव दिये, मैं नाम नहीं लूगा बल्कि यह कहूंगा कि कोई भी सडक जो अधूरी पड़ी हुई है और वहां मैटिरियल पड़ा हुआ है, उनको जल्दी बनाना चाहिये । अगर कोई सड़क किसी मंडी को जाती हो और किसी वजह से वह अधूरी रह गई हो जैसे एक सड़क का मैं उदाहरण देता हूं कि किरमच से शमशीपुर तक तीन किलोमीटर की एक सड़क गई, उसका मिट्टी ईंटों का सोलिंग और पुलियो का काम पूरा हो चुका है और उस पर सारा सामान पड़ा है सिर्फ कुटाई करने की बात है । ऐसा उन्होने से वहां पर पडा हुआ मैटिरियल खराब हो रहा है.... (विल)... इसलिये मेरी गुजारिश हैकि ऐसी–ऐसी जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको जल पूरा करें ताकि इससे आने–जाने की जो रुकावट पड़ी हुई है,

मंडियों में अनाज ले जाने की लोगो को जो सहूलियत नहीं है, वह शीघ्र हो सके । इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 24 जोकि टूरिजम के बारे में है, उसको लेता हूं । उसमें मैं तो यह समझता हूं कि जो टूरिजम के नाम पर काम किये गये हैं.....

Mr. Speaker : Please wind up. The Finance Minister has also to speak. At 5 P. M. the guillotine will be applied.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मैं थोड़ी सी देर और बोलूंगा । तो टूरिजम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं तो यह समझता हूं कि यह एक अन–प्रोडक्टिव खर्चा है और ये जो होटल, मोटल बनाए गए हैं ये तो सिर्फ पूंजीपतियों के मनोरंजन के लिये बनाये गये हैं । गरीब आदमी तो वहां चाय का प्याला भी नहीं पी सकता । इसलिये इस खर्चे को भी यदि आप बचा कर दूसरे कामों के लिये लगाए तो उससे और भी जल्दी तरक्की हो सकती है ।

डिमांड नम्बर 9 की बात मैं करना चाहता हुं, जोकि शिक्षा के बारे में है । वित्त मंत्री मन्त्री महोदय के शब्द मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं कि राज्य में 6 से 11 साल की आयु तक स्कूल? जाने वाले बच्चों की औसत, अखिलभारतीय औसत से कम है । यानी जहां तरक्की का ढिंढोरा पीटा जाता है वहां शिक्षा के मैदान मेंयह तरक्की है कि हम औसत भी पूरी नहीं कर सके जोकि बुनियादी चीज है । तो यह कोई अच्छीबात दिखाई नहीं. देती । मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और

निवेदन करूंगा कि इस कभी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि शिक्षा का प्रसार हो । स्पीकर साहब, आज की जो शिक्षा पद्धति है इस में आमूल–चूल परिवर्तन होना चाहिएं क्योंकि आज जो शिक्षा पद्धति है, उस की वजह से बेकारी बढ .रही है । आज अगर किसी राज का अनपढ़ लड़का उस के साथ जाकर रोज का काम करता है तो वह 10 से 15 रुपए दिहाड़ी के लेता है लेकिन दूसरी और जो सी0 ए0 पास करे उस को तीन सौ रुपए माहवार भी नहीं मिल पाते । और फिर कई बार नौकरी भी नहीं मिलती और वे बेकार फिरते रहते हैं । लेकिन इस के मुकाबले में जो अनपढ़ और अनजान लड़का है, वह सीमेंट भी उनका ही इस्तेमाल करता है, ईंटें भी उनकी ही खराब करता है लेकिन उन के सिर से ही 10–15 रुपए दिहाड़ी के लेता है । इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा पद्धति में ऐसी बातें आनी चाहिएं ताकि जब कोई विद्यार्थी शिक्षा संस्था को छोड़ कर जाए तो उस विद्यार्थी को आत्मविश्वास हो कि मैं ने नौकरी के पीछे नहीं भागना, मैं अपना काम करूंगा और उसे काम करने के लिए हमारी सरकार को सहूलियत देनी चाहिएं । चाहे वह कर्जे की शक्ल में हों, चाहे कच्चे माल कॉ शक्ल में हों, वह पूरी की जानी चाहिए । इस से एक तो बेरोजगारी दूर होगी और दूसरे देश में तरक्की होगी. इस के साथ–साय एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि कौल गांव के अंदर कृषि महा विद्यालय प्राईवेट तौर पर लोगों ने बनाया था जिस पर लोगों ने 10– 15 लाख रुपया खर्च किया और वहां से सैकड़ों लड़के कृषि में ग्रेजुएशन कर के निकले और

उनको काम भी मिला लेकिन तीन साल हुये वह महा विद्यालय कृषि विश्व–विद्यालय हिसार को किसी की गल्ती से दे दिया गया था और वह तब से ही बंद कर दिया गया है, पता नहीं उस का क्या कारण है लेकिन इस बार कहा गया है कि पहले और दुसरे साल कीशिक्षा यहां पर अगले साल से शुरु की जाएगी मगर इस से पहले जो तीन सालों में नुक्सान हो गया है उसकी पूर्ति तो हो ही नही सकती क्योंकि वहां से कम से कम 120 लड़के प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रविष्ट होते थे । इस प्रकार तीन वर्ष में तीन चार सौ कृषि स्नातकों को हानि हुई, वह जो घाटा हुआ है वह तो पूरा नहीं हो सकता मैं निवेदन करूंगा कि आगे के लिये आप लोगों का नुक्सान न करें और उस को पूरा डिग्री कालेज बना दें जैसे वह पहले बना हुआ था । उस गांव के लोगों ने 70 एकड़ जमीन सरकार के सपुर्द कर दी है इसलिए मैं एक बार फिर निभेदन करूंगा कि जब उन्होंने इतनी कुर्बानी की. है तो आप को जैसे वह महाविद्यालय पहले चल रहा था वैसे ही उसको आगे के लिए डिग्री तक, जरूर चालू करना चाहिए, पिछली जो घाटा हुआ वह तो चत्रो उन्होंने निपट लिया । जो कृषि स्नातक निकलते हैं, अगर वह अपना काम करना चाहें तो उनको भी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिएं और मैं निवेदन करूंगा कि जव वजीर साहब जवाब दे तो इस बात की ओर जरूर ध्यान दे और बताएं कि उनकी क्या–क्या सुविधाएं दी जाएंगी । अब मैं डिमान्ड नम्बर 10 पर, जो मैडीकल ऐड हैल्प के बारे में हे, कुछ सुझाव देना चाहूंगा । स्पीकर साहब, आजकल हस्पतालों के भवनों के जो नए

नस डिजाईन बनते हैं वह फैशउएवल तो होंगे लेकिन आप मैडीकल कालेज रोहतक में अगर खड़े होकर कर देखें, चाहे आप गैलरीज में भी खड़े क्यों न हों, वहां पर भी नेचुरल हवा नहीं लगती क्योंकि नेचुरल हवा के लिए जो छत के नजदीक रोशनदान होते हैं वह कहीं पर भी नहीं बनाए गए । मैं समझते हूं कि इस तरह से डिजाईन की बिल्डिंग में लोगो को बहुत बेआरामी होती हे । इस लिए मैं सुझाव दूंगा कि बिल्डिंग इस तरह की होनी चाहिए कि यदि बिजली भी न आए और पंखे भी न चलें तो भी कमरों के अन्दर बीमार अन्राम से रह सकें और उनको नेचुरल मिल सके आजकल तो यह हालत है कि तंदरुस्त आदमी भी वहां पर खड़ा नही हो सकता जो बीमार पड़ा है वह तो बेचारा तड़पता है । इसलिए ऐसी बिल्डिंगों के डिजाईम्ब को सुधारता जाए ताकि कुदरती हवा का आना–जाना ठीक तरह से हो । (घन्टी)

Mr. Speaker : You have taken sufficiently long time. Please wind up.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा, मैं तो सुझाव ही दे रहाहूं, कोई लम्बी चौड़ी तकरीर भी नही कर रहा तो इस के साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहत्ता हूं कि जो क्बालिफाईड डाक्टर्ज हैं, वे हर हस्पताल मे होने चाहिएं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई डाक्टर चला गया तो उस कीं जगह टूसरा नया डाक्टर आए ही नही अगर एक डाक्टर चला जाता है तो उस की जगह दूसरा डाक्टर भेजने का प्रबंध

बहुत जल्दी किया जाना चाहिए इस के साथ–साथ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए मैं यह कहूंगा कि कुरुक्षेत्र में जहां आयुर्वे दिक कालेज खुला हुआ है, वहां पर मैडीकल कालेज की भी जरूरत है । यह शिक्षा जितनी भी बढ़ाई जा सके बढ़ाई जानी चाहिए क्योकि जो विद्यार्थी वहां से शिक्षा हासिल कर के निकलेंगे, वे नौकरी ढूंढने की बजाए अपने पांव पर खड़े' होंगे और अगर कोई गांव का होगा तो वह गांव में दुकान खोल कर लोगों को चिकित्सा सुविधा देगा ।

इसके बाद मैं जल वितरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे हल्के नीलोखेडी मे अमीन गांव है जोकि बहुत ऊंचे पर वसा हुआ है और जो कुएं हैं वह बहुन नीचे है । इस लिए वहां से लोगों को पानी ले जाने में बहुत मुश्किल पेश आती है और बरसात के दिनों में तो उनको गलियों में सेचढ कर ले जाना बहुतही मुश्किल होजाता है । वहां से लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास करके भेजा है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जल वितरण की सुविधा दी जाए । वह गांव वैसे भी कुरुक्षेत्र के पास है और वहां पर ऐतिहासिक चक्रव्यू किला भी है (घण्टी)

Mr. Speaker : You have taken sufficiently long time. Please wind up. The Finance Minister will speak before 5 p.m.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक मिनट में खत्म कर दूंगा । डिमांड नम्बर 21 जो कम्युनिटी

डिवैल्पमैंट के बारे में है, इस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूगा जो मकान वनाने की योजना है इस में सरकार का ध्यान गांवों कर ओर भी जाना चाहिए और जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो हरिजन है ओर बैकचड है, उनको प्रैकैंस दी जानी चाहिए और देहातों को विशेथ तौर पर इस योजनामें शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि हरियाणा अगम तौर पर देहाती प्रदेश है । मैं आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिए है उन की और सरकार ध्यान देगी

वित मन्त्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तीन रोज बजट पर जनरल डिस्कशन हुई और अब डिमांडजु पर डिस्कशन हुई । इस में भी ज्यादातर वही बातें दोहराई गई हैं जो कि ओरिजनल डिस्कशन मैं हुई थीं लेकिन फिर भी मैं उनका जवाब दे देता हूं । यहां पर कहा गया कि हमारे बजट में 1973–74 के शुरू में 14.17 करोड़ का डैफिसिट था जो साल के आखिर में 5.19 करोड़ रह गया और अब आयदा साल के लिये जो बजट पेश किया गया उसमें 17.97 करोड़ रुपये का डैफिसिट है, इसे कैसे मेक–शप किया जायेगा । जिन्होंने यह एतराज किया वह मेरी बजट स्पीच को शायद सुनना या पढ़ना भूल गए । अगर वह उसे पढ़ें तो पता लग जायेगा कि उस में लिखा हुआ है कि जिस तरह से पहले अखराजात में कमी की गई है, किफायत की गई, कुछ टैक्सी की वसूली ज्यादा हुई, टै क्यों की वसूली के तरीके को सख्त किया गया और कई जगह पर कई

मदों में आमदनी बढा ली गई और यह डैफिसिट पूरा हुकर, उसी तरह से आयंदा भी किया जायेगा और यह बात मैंने अपनी बजट स्पीच में साफ कर दी हुई है । इस में लिखा हुआ है

"A substantial gap would, however, still remain which it is proposed to cover through economy in expenditure, better realisation of taxes and other dues and through some measures for additional mobilisation."

और फिर हमें जो सैट्रल फायनैंशियल असिस्टैसं मिलनी है, उसके बारे में अभी डिस्कशन होनी है और इस बारे में भी इस में लिखा है:

"Some of these estimates, like the Central assistance for the State Plan and market borrowings, are as yet tentative."

यह चीज अमी फाईनेलाइज नहीं हुई है और आंयदा रिसोर्सिज को भी मोबेलाइजेशन करने को बात इस में कही गई है । और इसमें वह सभी बातें आ जाती हैं जिन बातों से डर लगता है यानी इस में टैक्सिज भी आ जाते हैं और दूसरी बातें भी आ जाती हैं और आ सकती हैं. तो इस डैफिसिट से डरना नहीं चाहिये । यह ठीक है कि गवर्नमैंट इस पर पूरा ध्यान रखेगी कि इस डैफिसिट को कम किया जाये । एक मैंबर साहब ने कहा था कि रोडज बनाने का काम रुक गया है । मैं कहना चाहता हूं कि यह काम बिल्कुल नही रुका है, जरा रफ्तार धीमी हो गई है और वह इस लिये हो गई है कि जिस वक्त देखा गया कि बजट में

डैफिसिट भी है, ऐडवर्स सरकमस्टांसिज भी हैं तो अनप्रोडस्टिव अखराजात और काम कम कर दिये गये लेकिन जो प्रोडक्टिव काम हैं, जरूरी काम हैं, वह ज रखे गये है । यह बात नहीं है कि बंद कर दिये गये हैं । रोडज का काम भी इसलिये जरा धीमा किया गया है क्योंकि और जरूरी कामों–इरीगेशन विजली वगैरा को प्रायर्टी देनी थी ।

गेहूं की थोक–फरोशी पर भी एतराज किया गया है । अगर सरकार यह थोक–फरोशी का काम अपने हाथ में न लेती तो जो नतीजे निकलते वह ज्यादा भयानक होते । कई प्रांतों के अन्दर सूखा आया हुआ था जैसे महाराष्ट्र राजस्थान बगैरा में । जुलाई के महीने में मैं फायनैंस मिनिस्टर्ज कान्फैसं में कश्मीर गया हुआ था तो वहां एक प्रांत के मिनिस्टर साहव ने मुझ से कहा कि मित्तल जी, कहीं आप हमें भूखा तो नहीं मारोगे । मैं उनकी बात को समझ गया कि इनके प्रांत में सूखा है मैंने उन से कहा कि हम भूखे रह जायेंगे लेकिन आप को भूखा नहीं मरने देंगे । मेरे कहने का मतलब यह है कि उस वक्त अगर हम थोक फरोशी अपने हाथ मे न लेते तो इसके दो नतीजे निकलते या तो यहां से सारा गेहूं बाहर चला जाता और जव यहां पर लोगों को खाने को न मिलता तो उस वक्त यह लोग जो कहते हैं कि थोक–फरोशी क्यों ली, यह कहते कि बाहर जाने से क्यो नहीं रोका और फिर दूसरी बात यह होती कि जब गेहुं फसल पर एकदम से मार्किट में आता है तो मंडियों में कम भाव किसानों को दिया जाता है तो

थोक–फरोशी हाथ में न लेने से किसान को उसके गेहूं के पूरे पैसे न मिलते । तो इन सब बातों को सोच कर सरकार ने पहले साल 76 रुपये स्पोर्ट प्राईस गेहूं की मुकरर्र की थी । यह स्पोर्ट प्राईस थी और किसान को हक था कि अगर उसे ज्यादा कीमत मिले तो उस पर बेच दे लेकिन अगर उसे 76 रुपये से कम कीमत मिलती है तो सरकार ने कहा कि वह 76 रुपये में लेने के लिये तैयार है इससे कम भाव नहीं होने देगी यानी 76 रुपये की गारंटी किसान को दे दी । फिर जव 76 रुपये पर भी एतराज किया गया तो फिर सरकार ने इस साल के लिये 85 रुपये स्पोर्ट प्राईस मुकरर्र कर दी । जव हम ज्यादा भाव करने की वात कहते हैं तो हमें एक बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिये कि कई ऐसी जगहें हैं, प्रांत हैं, जहां पर लेबर रहती है, इण्डस्ट्रीज चलती हैं और प्रांत में गरीब लोग भी रहते है ' तो उनको अगर मुनासिब कीमत पर चीजें खाने–पीने की नहीं मिलतीं तो उनको तकलीफ होगी । जो गरीब तबके हैं, वह तो यह कहते हैं कि सरकार ने ठीक किया है । सरकार ने तो दोनों बातों को देखना है कि को भी उसकी प्रोडयूस को मुनासिब कीमत मिले और उसके साथ आम जनता को भी खाने–पीने की चीजें मुनासिब कीमत पर मुहैया होनी चाहिये । इन तमाम बातों को देख कर यह नीति सरकार ने अपनाई है वरना कोई जरूरत नहीं थी कि सरकार यह झगड़ा मोल लेती । जैसा हमारा समाज बन रहा है, उस समाज के लिये जरूरी हो जाता है कि होल–सेल ट्रेड को जो जरूरी चीजों को है, उसे हाथ में लिया जाये ।

फिर यहां पर कहा गया कि ग्रामोद्योग करे उन्नत किया जाये । मैं भी इस बात की ताईद करता हूं कि ग्रामोद्योग को पूरी सहायता मिलनी चाहिये लेकिन ग्रामोद्योग तभी पनपेंगे जव हम इन को अपनायेगे । इनकी वनी चीजों को इस्तेमाल मे लायेंगे । गांव की बनी चीजो को खरीदेंगे लेकिन अगर हम चीजें तो इस्तेमाल करें मशीनों की बनी हुई और गीत गायें ग्रामोद्योग के और हमदर्दी जताये गांव के लोगों से तो यह फीकी हमदर्दी ही होगी, कोई भलाई होने वाली बात नहीं होगी । अगर कोई गांव में रहने वाला मोची जूती बनाये तो जो लोग ग्रामोद्योग की बातें करते हैं, वह शायद उस जूती को खरीदने के लिये तैयार नहीं होंगे और बाटा की बनी हुई जू ती ही खरीदेगे । इसी प्रकार से कपडे की वात है । किसी जमाने में महात्मा गांधी जी ने खद्दर करे चलाया । उनको ख्याल था कि विलेज इको– नोमी सैल्फ–सफीशैंट होनी चाहिये और इसे कहोने पोलिटीकल ए पन के तौर भी इस्तेमाल किया मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं पढा करता था । 1920–21 की बात है कि एक कारटून निकला था कि गांधी जी चरखा कात रहे हैं और उस में से बम्ब निकल रहे हैं, जो मांचौस्टर और लंकाशायर में जाकर टैक्सटाइल मिल्ज पर जाकर गिर चे हैं । वह बात यह थी कि महात्मा जी के विदेशी विलायती कपड़ा पर वैन से वाईकाट से वहां के कारखाने बंद हो रहे थे । जब गांधी जी वहां लंडन में राउंड टेबल कान्फैस मै गये तो उनको वहाँ के कारखाना वालों ने इनवाईट किया और कहा कि आओ, बात करो और यह झगड़ा खत्म करो, यह बैन उठाओ ताकि उनके काम चले । आज

जो खद्दर पहनते हैं, उन पर अंगुली उठाई जाती है और कहा जाता है कि यह कांग्रेसी है, यह है, वह है मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम ग्रामोद्योग कॉ सही मायनो में तरक्की चाहते हैं तो हमें इन उद्योगो के बने कपड़ों ओर दूसरी चीजों को खरीदना चाहिये, इस्तेमाल करना चाहिये । जो भाई उधर बैठे हैं, हम तो खरीदते है इस्तेमाल करते है, उन से कहूंगा कि उनको भी चाहिये कि वह खद्दर पहने, तभी इन ग्रामोद्योग की तरक्वी होगी, जिन के लिये यह हमदर्दी जताते हैं वरना यह लिप्स सिम्पथी ही होगी सरकार क्या करे? सरकार तो सब कुछ कर रही है । एक कमीशन बिठा रखा है और हर प्रांत में एक बोर्ड बना रखा है इसके लिये और लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है । और गवर्नमैंट और भी ज्यादा मदद करने के लिये तैयार है लेकिन आप लोग भी तो इन चीजों को अपनाओ । हम चीनी के वर्तनों में खाना–खाना चाहतेहैं और गांव का कुम्हार जो बर्तन बनाता है, वह नहीं लेते है । मेरे कहने कॉ मतलब है कि सुझाव के तौर पर तो इनकी वात ठीक है लेकिन महज सुझाव दे. देने से ही काम नहीं चलेगा, कोरा सुझाव कुछ सहायता नहीं कर सकता, इन चींजों को जो ग्रामोद्योग में वनका हैं, उनका इस्तेमाल भी सव को करना चाहिये बिजली के ऊपर काफी बहस हुई और इसके लिए कई सुजैशन भी आई हैं कि कोशिश

18.00 बजे ।

यह हो कि ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको काम में लाएं । यह ठीक बात है लेकिन यह सब हमारे हाथ में नहीं है । कई दफा बिजली की इररैगुलर सप्लाई होती हूँ । कई दफा पावर फेल हो जाती है । इन चीजों का असर पड़ता है । इसके वावजूद भी सरकार की यह कोशिश है कि बिजली ज्यादा से ज्यादा मिले ज्यादासे ज्यादा पावर हाउसिज हों । जिस टाईप के भी बन सकतें हैं वह बनाए जाएं

पशुओं के बारे में नीलोखेडी के बारेमे ट्रांसपोर्ट के बारे में भी सदस्यों ने अपने विचार दिए इन सब बातों पर विचार किया जाता है । जो जरूरी बातें होगी, अगर रुपया पैसा मुहैया होगा तो सब बातें अमल में आएगी, लेकिन. इस वक्त कोई बात नजर नहीं आती । चौधरी. अमर सिंह ने रेट आफ इन्ट्रैस्ट के बारे में बतलाया इस को देख त्रिया जाएगा कि क्या बात है । वैसे तो कोई खास बात नहीं है । स्पीकर साहब, दो सदस्यों के सिवाय सभी सदस्यों ने वजट पर अच्छी अच्छी बातें कही । मैं आप से निवेदन करूंगा कि अव डिमांड्ज पर वोट लिए जांए ।

Mr. Speaker : There are 25 demands, 1 to 25. I am putting them all together.

Question is—

That a sum not exceeding Rs. 19,67,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 1 Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 3,74,19,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 8,37,92,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 3—Home Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,75,37,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 4—Reven ue Department.

That a sum not exceeding Rs. 94,69,070 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1 974-75 in respect of the charges under Demand No. 5—Excise and Taxation Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,70,60,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 6—Finance Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,64,12,306 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 19,52,26,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 8—Buildings and Roads Department.

That a sum not exceeding Rs. 27,84,80,170 he granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 9—Education Department.

That a sum not exceeding Rs. 13,97,27,370 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 10—Medical and Public Health Departments.

That a sum not exceeding Rs. 14,19,09,180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 11—Urban Development Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,62.27,090 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 12—Labour and Employment Departments.

That a sum not exceeding Rs. 2,60,20,770 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation Departments.

That a sum not exceeding Rs. 95,77.75,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course o? payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No.14—Food and Supplies Department.

That a sum not exceeding Rs. 45,64,19,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 15—Irrigation Department .

That a sum not exceeding Rs. 2,76,38,010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 16—Industries Department

That a sum not exceeding Rs. 11,00,95,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year

1974-75 in respect of the charges under Demand No. 17—Agriculture Department.

That a sum not, exceeding Rs. 3,30.92,950 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 18— Animal Husbandry' Department.

That a sum not exceeding Rs. 24,72,980 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 19—Fisheries Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,38,01,970 be

granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 20—Forest Department.

That a sum not exceeding Rs. 2,34,22,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under 11 errand No. 21—Community Development Department.

That a sum not exceeding Rs, 3,58,93,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1-974-75 in respect of the charges under Demand No. 22—Co-operation Department.

That a sum not exceeding Rs. 21,60,06,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No. 23—Transport Department.

That a sum not exceeding Rs. 1,82,68.800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974,75 in respect of the charges under Demand No. 24—Tourism Department.

That a sum not exceeding Rs. 28,54,26,220 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1974-75 in respect of the charges under Demand No.25—Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

17.04 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 17th January, 1974)